सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 180 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 14 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

अम्बेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और रायपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रायपुर के अंबेडकर चौक पर 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया और समरसता भोज में शामिल होकर सामाजिक समानता का संदेश दिया। साय ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने की अपील की।

महिलाओं को प्रतिमाह 2000, 3 फ्री सिलेंडर और ब्याज-मुक्त लोन

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें महिलाओं के लिए 2000 रुपये, साल में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री देने का वादा किया। जेपी नड्डा ने चुनावों से पहले बीजेपी का घोषणापत्र जारी किया। इस कार्यक्रम में नड्डा के अलावा तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, तमिलिसाई सौंदरराजन और बीजेपी नेता के अन्नामलाई मौजूद थे। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने तमिलनाडु नव वर्ष के मौके पर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करने का फैसला लेकर एक अच्छा कदम उठाया है।

ईरान से 7 साल बाद भारत आया कच्चा तेल, पहुंचे दो टैंकर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच सात साल बाद ईरान से कच्चा तेल लेकर दो सुपर टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। यह टैंकर पश्चिम और पूर्वी दोनों तटों के बंदरगाहों पर आए हैं। शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार सात साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरानी कच्चा तेल लेकर कोई टैंकर भारत पहुंचे हों। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत उससे कच्चा तेल नहीं खरीद पा रहा था। नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी का एक विशाल कच्चा तेल टैंकर फेलिसिटी 12 अप्रैल देर रात गुजरात के सिक्का बंदरगाह पर आकर डॉक हुआ। यह ईरान की खर्ग द्वीप से करीब 20 लाख बैरल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था।

बच्चों ने संभाली शहर की ट्रैफिक, बने एम्बेसडर; पुलिस की अपील - अपनी बेइज्जती न कराएं पालक

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। बिलासपुर में सोमवार को चौक-चौराहों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से लेकर सड़क तक, हर जगह स्कूली बच्चे सक्रिय नजर आए। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर पुलिस ने स्कूली छात्र-छात्राओं को पुलिसिंग की दुनिया से रूबरू कराया।

इस दौरान छात्रों ने न सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम को समझा, बल्कि खुद कंट्रोल रूम में बैठकर पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के साथ लाइव अनाउंसमेंट भी किया। राहगीरों को नियमों का पालन करने की अपील की।

एसएसपी रजनेश सिंह ने लाउड स्पीकर के जरिए आम लोगों से कहा

कि, आज ट्रैफिक सिस्टम बच्चे संभाल रहे हैं, आपको देखकर सीख रहे हैं। कृपया नियमों का पालन करें और उनके सामने अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। यह संदेश सुनते ही कई जगह वाहन चालकों ने हेलमेट पहना, लाइन में खड़े हुए और ट्रैफिक नियमों का पालन करते नजर आए।

छात्रों को शहर के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ले जाया गया, जहां उन्होंने आईटीएसएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम), लाइव सीसीटीवी निगरानी, नंबर प्लेट और फेस रिकग्निशन सिस्टम को खुद ऑपरेट कर देखा। कुछ छात्रों ने तो सीधे सिस्टम से अनाउंसमेंट कर अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों को हिदायत भी दी।

'अपने हक के लिए बेटियां सालों तक इंतजार नहीं कर सकतीं'; पीएम मोदी ने महिलाओं के नाम लिखी खुली पाती

नई दिल्ली (ए.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देश की महिलाओं के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। मोदी ने लिखा कि अगर 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग पूरे आरक्षण के साथ होते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत और जीवंत हो जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि विधायी संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। भारत की बेटियों से उस चीज के लिए हमेशा इंतजार करने को नहीं कहा जा सकता, जो उनका हक है।

एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा- यहां भारत की 'नारी शक्ति' के नाम मेरा पत्र है, जिसमें मैं उस वादे को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहरा रहा हूं, जो दशकों से लंबित था। मैंने अपने साथी नागरिकों के साथ उस संकल्प को जल्द ही साकार करने के विषय पर अपने विचार साझा किए हैं।

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर एक नजर

सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किया गया था, जिसे आम तौर पर 'महिला आरक्षण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। मौजूदा कानून के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ था।

इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने के लिए, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव की जरूरत थी; इसलिए, सरकार कानून में संशोधनों को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है।

मोदी की बातें तीन बिन्दुओं में

- जब महिलाएं कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही हैं, तो यह बिल्कुल सही है कि विधायी संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े।
- 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए पूरे आरक्षण के साथ होते हैं, तो लोकतंत्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा।
- मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखें और इस ऐतिहासिक संसद सत्र में हिस्सा लेते समय उनका हौसला बढ़ाएं।

सीधी का संस्कारी चोर, जूते उतारे, हाथ जोड़े फिर चुरा लिया चांदी का मुकुट

सीधी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने पुलिस और जनता दोनों को हैरत में डाल दिया है। एक शातिर चोर ने शहर के एक हनुमान मंदिर को निशाना बनाया, लेकिन उसका तरीका किसी पेशेवर अपराधी से बिल्कुल अलग था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर ने मंदिर की मर्यादा का पूरा पालन किया। जूते बाहर उतारे, भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना की और फिर मौका पाकर चांदी का आधा मुकुट और अन्य आभूषण लेकर चंपत हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित इस मंदिर में चोर ने एक नहीं बल्कि दो बार धावा बोला। पहली कोशिश 8 अप्रैल को की। चोर मंदिर पहुंचा, जूते बाहर उतारे और हनुमान जी के मुकुट पर हाथ साफ करने की कोशिश की। नाकाम रहने पर वह पीछे स्थित शनि मंदिर गया, वहां भी सिर झुकाया और चांदी का मुकुट लेकर चला गया।

धमाके की साजिश नाकाम, जिलेटिन-आईईडी बरामद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर/नुआपाड़ा। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर धेकुनपानी के घने जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद किया गया है। इससे क्षेत्र में एक संभावित बड़े हमले की साजिश को विफल कर दिया गया है।

ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में कोमना पुलिस शिविर से संचालित सीआरपीएफ की एक टीम ने यह कार्रवाई की। खुफिया जानकारी के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। यह जंगल सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है,

जिसका उपयोग नक्सली करते रहे हैं।

तलाशी के दौरान 70 जिलेटिन स्टिक बरामद हुईं। ये जिलेटिन स्टिक आईईडी विस्फोटों के लिए नक्सलियों द्वारा अक्सर उपयोग की जाती हैं। इसके साथ ही तीन स्टील कंटेनर और चार बिजली तारों के बंडल भी मिले। अधिकारियों का मानना है कि इन सामग्रियों का उपयोग सुरक्षा बलों को निशाना बनाने या बड़े पैमाने पर आईईडी हमला करने के लिए किया जा सकता था। समय पर हुई बरामदगी से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है।

सुरक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि सुनाबेड़ा अभयारण्य और उसके आसपास के जंगल माओवादियों द्वारा लंबे समय से छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। हालांकि, इस क्षेत्र को हाल ही में काफी हद तक माओवादी मुक्त घोषित किया गया था। इससे वन्यजीव संरक्षण और विकास पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला था। वरिष्ठ सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि ऐसी बरामदगी नक्सलियों की रसद क्षमताओं को काफी कमजोर करते हुए उन्हें हतोत्साहित करती हैं।

सीएम साय ने सांसदों-विधायकों को लिखा पत्र

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा को लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण बताते हुए कहा है कि यह मातृशक्ति

को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कि इस अधिनियम का पारित होना लोकतंत्र की एकजुटता और महिला सशक्तीकरण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2029 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पूर्व इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मातृशक्ति को उनका समुचित अधिकार शीघ्र प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधायकों से कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का समय आ गया है। 'मातृशक्ति के नेतृत्व में सशक्तीकरण' का यह अभियान देश के समग्र विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जमीन सौदे में ले लिए 11 लाख, रजिस्ट्री से मुकरा

- कोर्ट के आदेश पर 4 लोगों पर एफआईआर, 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग-भिलाई। पाटन क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। एक व्यक्ति से 11 लाख रुपए लेने के बाद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। महीनों की टालमटोल के बाद मामला कोर्ट पहुंचा, जिसके आदेश पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर

दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम अंगारी जिला बालोद निवासी अश्वनी कुमार डडसेना ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि, ग्राम केसरा, तहसील पाटन स्थित 0.93 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए आरोपियों से 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। उन्होंने गणेश्वर सिन्हा के खाते में 5 लाख रुपए और नीलमनी व खेमीन सिन्हा के खातों में 3-3 लाख रुपए जमा कराए। पूरी राशि मिलने के बावजूद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की।

आरोपी किसी ने किसी बहाने रजिस्ट्री को टालते रहे। परिवादी लगातार आरोपियों से संपर्क कर रजिस्ट्री कराने की मांग करते रहे। हालांकि, आरोपियों ने हर बार अलग-अलग बहाने बनाकर प्रक्रिया को टाल दिया। इसके बाद परिवादी ने कोर्ट का रुख किया, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया।

राज्यसभा उपसभापति के लिए 17 अप्रैल को चुनाव

नई दिल्ली। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए 17 अप्रैल को चुनाव होगा और सत्तारूढ़ राजग (एनडीए) द्वारा हरिवंश को इस महत्वपूर्ण पद पर फिर से निर्वाचित कराने का प्रयास किए जाने की संभावना है। हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो गया था। इसके बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरिवंश को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया और उन्होंने 10 अप्रैल को शपथ ली। वहीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद 2019 से रिक्त है।

ट्रक से भिड़ी बस; चालक ने पत्नी और पुत्र सहित गंवाई जान

अलवर (ए.)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे मंगलवार तड़के एक बार फिर मातम का गवाह बना। अलवर जिले के पिनान के पास सुबह करीब 5 बजे एक निजी ट्रेवल बस और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में बस चालक, उसकी पत्नी और मासूम बेटा शामिल है। इस हृदयविदारक हादसे में 33 अन्य यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, 'स्लीपर' ट्रेवल बस सोमवार रात करीब 9 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना

हुई थी। हादसे के वक्त यानी सुबह 5 बजे, बस में सवार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। पिनान में चैनल नंबर 100 इंटरचेंज पुलिया के पास बस अचानक आगे चल रहे केमिकल से भरे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भयावह थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया।

बस चालक अपने साथ अपनी पत्नी और दो बच्चों को भी ले जा रहा था। इस टक्कर में ड्राइवर, उसकी पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि, कुदरत का करिश्मा ही था कि ड्राइवर की तीन वर्षीय मासूम बेटी को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने सुरक्षित बची बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।

हादसे के कारण एक्सप्रेस-वे पर कुछ घंटों के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर रास्ता साफ कराया। फिलहाल मृतकों के शवों को रैणी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है।

इरान की मध्यस्थता में भारत की मदद को आपसी दुश्मनी भुलाकर साथ आए आर्मेनिया-अजरबैजान

नई दिल्ली (एजेंसियां)। पश्चिम एशिया संकट में भारत को ऐसे देशों का भी साथ मिला है, जो आपस में अपनी कट्टर दुश्मनी की वजह से दुनिया भर में कुख्यात रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान ऐसे ही मुल्क हैं, जिन्होंने पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है और ईरान ने भी इसमें तालमेल बिठाने में सहायता की है।

इकोनॉमिक टाइम्स को मिली जानकारी के अनुसार आर्मेनिया ने पिछले हफ्ते मछुआरों की स्वदेश वापसी में मदद की है, वहीं अजरबैजान ने भी ईरान युद्ध के दौरान तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से 32 स्टाफ और उनके परिवार वालों को भारत लाने में सहायता पहुंचाई है।

आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की दुश्मनी चार दशकों से भी पुरानी है। दोनों आपस में युद्ध भी लड़ चुके हैं।

ईरान ने ऐसे करवाई भारतीयों की मदद

6 अप्रैल, 2026 को विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर भी बताया था कि ईरान की सहायता से आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते लगभग 1,800 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। पिछले हफ्ते इन्हीं दोनों देशों ने भारतीय मछुआरों और तेहरान के दूतावास से भारतीयों को स्वदेश भेजने में मदद की है।

दोनों के बीच शांति समझौते की कोशिशें भी हुई हैं। लेकिन, हालात पूरी तरह मधुर कभी नहीं रहे हैं। लेकिन,पश्चिम एशिया में युद्ध का वक्त आया तो दोनों से जितना बन पड़ा भारत की मदद करने में भरपूर सहयोग की कोशिश की है।

भारत का बहुत ही भरोसेमंद दोस्त है आर्मेनिया

आर्मेनिया भारत का भरोसेमंद मित्र है। दोनों देशों में 1992 से ही द्विपक्षीय रिश्ते रहे हैं, जो गर्मजोशी वाले हैं। यह भारतीय हथियारों और रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक बनकर भी उभरा है। दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी भी मजबूत हो रही है।

अजरबैजान से भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा रिश्ता

पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक अजरबैजान के साथ भी भारत ताल्लुकात अच्छे ही थे। लेकिन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने तुर्की के चक्कर में फंसकर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया तो भारत के साथ एक दरार पैदा हुआ। पर अब यह पटने लगी है।

संपादकीय

श्रमिक अशांति

महंगाई और स्थिर वेतन के बीच बढ़ी खाई

कोरोना संकट के बाद पटरी पर लौटती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को दुनिया के कई भागों में जारी युद्ध व संघर्ष ने फिर पटरी से उतार दिया है। महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा मानवता और आम आदमी के जीवन पर भारी पड़ी है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं और यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित जरूर किया, लेकिन उसका असर उतना व्यापक नहीं था, जितना खाड़ी युद्ध का रहा है। जाहिरा तौर पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से आम आदमी के जीवन पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जीवन शैली व थाली पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों और इस्राइल की आक्रामकता से उपजे खाड़ी संकट ने एशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को संकट में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र की विफलता के चलते आज दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। जिसका सीधा असर महंगाई वृद्धि के रूप में सामने आया है। एक ओर ईंधन संकट और उससे बुरी तरह प्रभावित जनजीवन आक्रोश का कारक बना है। विडंबना यह है कि इस महंगाई के बीच कामगारों के वेतन सिकुड़ने लगे हैं। जीवनयापन कठिन होते और कोई समाधान न निकलते देख श्रमिकों का आक्रोश सड़क तक पहुंचने लगा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में फैक्ट्रियों के श्रमिकों द्वारा किया गया हिंसक प्रदर्शन इस संकट की परिणति ही है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की औद्योगिक नगरी मानेसर में भी पुलिस व श्रमिकों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं। ये टकराव भारतीय औद्योगिक तंत्र की विसंगतियों की ही याद दिलाते हैं। इस तरह के हिंसक संघर्ष हमारी कानून-व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करते हैं। वहीं बताते हैं कि श्रमिक वर्ग, उद्योग और राज्य सरकार के बीच कहीं न कहीं संवाद की कमी है। यही वजह है कि वेतन बढ़ाने की मांग के समर्थन में शुरू हुआ मार्च कालांतर आगजनी, तोड़फोड़ व यातायात बाधित करने में तब्दील हो गया। निश्चित तौर पर समय रहते इस श्रमिक असंतोष को भांपते हुए बेहतर ढंग से संवाद किया जाता तो शायद टकराव की स्थिति पैदा न होती। दरअसल, सरकारों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि देश में ईंधन व गैस आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन जमाखोरी व प्रशासन की उदासीनता से इसकी कालाबाजारी जारी है। श्रमिक वर्ग जो छोटे गैस सिलेंडरों से जीवन-यापन करता था, उसमें व्यवधान पैदा हो गया। नियंत्रित गैस आपूर्ति से छोटे गैस सिलेंडर भरने का धंधा ठप हो गया। शायद सरकारों को भी इस बात का अहसास नहीं था कि कितना बड़ा श्रमिक वर्ग छोटे गैस सिलेंडरों को भरने के काले धंधे पर निर्भर है। यही वजह है कि हिमाचल समेत कई राज्यों में खाना पकाने के संकट के चलते श्रमिकों के घर लौटने के मामले प्रकाश में आए हैं। लेकिन इस संकट को शासन-प्रशासन के स्तर पर गंभीरता से नहीं लिया गया। निर्विवाद रूप से बढ़ती महंगाई और स्थिर वेतन के बीच बढ़ती खाई से अशांति की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। औद्योगिक केंद्रों में कामगार पश्चिम एशिया युद्ध के चलते बढ़ी महंगाई के कारण दबाव में अपना गुजारा करने के लिये संघर्ष कर रहे हैं। निस्संदेह, हरियाणा द्वारा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय इस गंभीर वास्तविकता की स्वीकृति को ही दर्शाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि तात्कालिक उपाय के रूप में बातचीत और शिकायतों का फौरी निवारण कारगर विकल्प नहीं हो सकते। हालांकि, अधिकारी अशांति फैलाने में निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं व्यवस्थागत अविश्वास को भी दर्शाती हैं। दरअसल, श्रमिकों का उपेक्षित महसूस करना वातावरण को अस्थिर बनाता है। लेकिन यह एक हकीकत है कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिये विनिर्माण की महत्वाकांक्षाएं स्थिर-प्रेरित कार्यबल के बिना संभव नहीं हैं। औद्योगिक अशांति केवल उत्पादन-निवेश तक ही सीमित नहीं रहती। इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और निवेशकों का भरोसा कम होने की आशंका भी पैदा होती है। निस्संदेह, आर्थिक प्रगति समावेशी हो। शासन को श्रमिक हितैषी होना चाहिए। विश्वास निर्माण से ही हमारे कारखाने विकास का इंजन बन सकते हैं।

> "संयुक्त राष्ट्र की विफलता के चलते आज दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। जिसका सीधा असर महंगाई वृद्धि के रूप में सामने आया है। एक ओर ईंधन संकट और उससे बुरी तरह प्रभावित जनजीवन आक्रोश का कारक बना है। विडंबना यह है कि इस महंगाई के बीच कामगारों के वेतन सिकुड़ने लगे हैं। जीवनयापन कठिन होते और कोई समाधान न निकलते देख श्रमिकों का आक्रोश सड़क तक पहुंचने लगा है।

आखिरकार सुनी गई आधी आबादी की आवाज़

आर. विमला, आईएएस

■ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं का न्यायोचित स्थान'

■ जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो भारत मजबूत होता है। घर की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज़ तक, यह एक नए और आत्मविश्वास से भरे भारत की परिकल्पना है। – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारत की महिलाएँ सदैव महान कार्यों में सक्षम रही हैं। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी ने बड़े-बड़े दार्शनिकों को निरुत्तर कर दिया था। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर ने जिस न्यायपूर्ण तरीके से अपने राज्य का शासन चलाया, उसकी बराबरी उनके समकालीन शासक नहीं कर सके। रानी लक्ष्मीबाई साहस की एक अमर मिसाल बन गईं। फिर भी, स्वतंत्र भारत—जो समानता के सिद्धांत पर आधारित एक संवैधानिक गणराज्य है ने इन महान महिलाओं की उत्तराधिकारियों को अपनी विधायिकाओं में शायद ही कोई जगह दी। पहली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 4.4 प्रतिशत थी। सात दशक बाद, 17वीं लोकसभा में भी यह आंकड़ा बढ़कर केवल 14.4 प्रतिशत तक ही पहुँच पाया। व्यक्तिगत प्रतिभा ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन व्यवस्थागत बदलाव अभी भी नहीं आया था। असल में, महिलाएं अपने ही लोकतंत्र में एक तरह से 'मेहमान' बनकर ही रह गईं। हमारे संविधान ने पहले ही दिन से यह स्वीकार किया था कि जब सदियों से ढांचागत विसंगतियां जड़ जमाए बैठी हों, तो केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होती। 'संरक्षणात्मक भेदभाव' के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बाद में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था सफल रही है: 24 मार्च 2026 तक, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 49.75 प्रतिशत महिलाएँ हैं। जिन जगहों पर महिलाएँ शासन करती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति सुचारू होती है, साफ-सफ़ाई की स्थिति बेहतर होती है और लड़कियाँ स्कूल जाना जारी रखती हैं। इसके बावजूद, संसद में भी इसी सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से जो विधेयक पेश किए गए थे, वे राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में दशकों तक बार-बार निष्प्रभावी होते रहे।

वह क्षण जिसने सब कुछ बदल दिया -

वह अधूरी कड़ी 19 सितंबर 2023 को पूरी हुई। भारत के नए संसद भवन में आयोजित कामकाज के पहले ही सत्र में, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के सर्वसम्मत समर्थन से पारित किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पेश करते हुए दोनों सदनों को बताया: यह कानून केवल एक कानून नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय महिला की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य के प्रति एक श्रद्धांजलि है।

यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उप-कोटा भी शामिल है। नए संसद भवन का यह पहला अधिनियम होना अपने आप में एक घोषणा थी: अमृत काल के लोकतंत्र की संरचना पूरे भारत के लिए और सभी की भागीदारी के साथ निर्मित की जाएगी।

इस अधिनियम में बदलाव लाने की अपार क्षमता है, क्योंकि इसके लागू होने से संसद में महिला सदस्यों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। महिला विधायक निरंतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं—ये वही क्षेत्र हैं, जहाँ भारत में लैंगिक असमानता सबसे अधिक है। एक ऐसी संसद, जिसमें एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी, वह अलग तरह के प्रश्न पूछेगी और अलग तरह के विचार सुनेगी। इससे भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होगा, न कि केवल उसकी बाहरी छवि में।

गरिमा से लोकतंत्र तक की यात्रा

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह समझा है कि ज़मीनी स्तर पर सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक सशक्तिकरण खोखला होता है। उनके द्वारा शुरू की गई यह यात्रा अत्यंत बुनियादी गरिमा से लेकर सर्वोच्च लोकतांत्रिक भागीदारी तक एक सुविचारित पथ पर आगे बढ़ती है। इसकी शुरुआत एक शौचालय से हुई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए 10 करोड़ घरेलू शौचालयों ने उन महिलाओं को सुरक्षा और आत्म-सम्मान लौटाया, जिन्हें लंबे समय से इन दोनों से वंचित रखा गया था। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण घरों तक नल का पानी पहुँचाया। महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पानी ढो कर लाने से मुक्ति मिली जिससे उनका सुबह का कीमती समय जाया हो जाता था। 'पीएम उज्ज्वला योजना' के 10.56 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों ने महिलाओं को धुएं से भरी रसोई से मुक्ति दिलाई। पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर घर बनाए गए। 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले जन धन खातों ने उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की। 'मुद्रा' योजना के ऋण, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, सखी, वन स्टॉप सेंटर और तीन तलाक का उन्मूलन: प्रत्येक योजना उसी सीढ़ी का अगला पायदान थी, जो उन्हें केवल गुज़ारा करने की स्थिति से गरिमा की ओर, गरिमा से सामर्थ्य की ओर, और सामर्थ्य से नेतृत्व की ओर निरंतर बढ़ाती गई।

आधुनिक भारत के लिए एक दृष्टिकोण

भारत को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। यह हमारे दौर के सबसे अधिक परिवर्तनकारी संभावित सुधारों में से एक है। महिलाओं के विधायी प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर, यह हर स्तर पर नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा: चाहे वे बजट हों जो मातृ स्वास्थ्य के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, वे कानून हों जो पीड़ितों की रक्षा करते हैं, या वे नीतियां हों जो लड़कियों को स्कूल में बनाए रखती हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'विकसित भारत' (2047 तक एक विकसित भारत) का दृष्टिकोण इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक उसके आधे नागरिक उन जगहों से बाहर रहें जहाँ सत्ता का संचालन होता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है: भारत तभी एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब इसकी महिलाएँ न केवल अपने घरों में, बल्कि अपनी संसद में भी पूरी तरह सशक्त होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय महिलाओं के लिए कुछ नया सृजन नहीं करता है। इसने उस विद्वत्ता, साहस और नेतृत्व करने की इच्छाशक्ति के लिए एक संस्थागत स्थान सुनिश्चित कर दिया है, जो महिलाओं में पहले से ही मौजूद है। शौचालय की गरिमा से लेकर संसद में समान आवाज़ तक, यह मात्र एक विधायी यात्रा नहीं है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जिसने अंततः पूर्णता की ओर बढ़ने का निर्णय लिया है। आधी आबादी को आखिरकार सुना गया। नज़रिया साफ है। ये मुहीम जारी रहेगी।

(लेखिका महाराष्ट्र सरकार में रेजिडेंट कमिश्नर एवं सचिव पद पर कार्यरत हैं और आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हैं)

गर्मियों में महंगे यात्रा खर्च से बचने के लिए 'होम स्वैप' पर विचार करें

एन. रघुरामन

2026 की गर्मियां आते-आते यात्री एक कठिन आर्थिक स्थिति झेल रहे हैं। अमेरिका में लोगों को लग रहा है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो रहा है। इधर, भारत में साधारण संतरा और सेब के दाम भी अल्फांसो आम के स्तर पर पहुंच गए हैं। ये बढ़ोतरी अचानक नहीं हुई, बल्कि यह पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर ईरान से जुड़े हालात के कारण आपूर्ति में आए व्यवधान का सीधा परिणाम है। इससे अब अंतरराष्ट्रीय आयात कम होने लगा है। असर बाजारों में साफ दिख रहा है।

पूरे देश में जूस की दुकानों के लिए जरूरी ईरान और मिस्र के संतरों की कम आवक से 15 किलो की पेटी के दाम 1400 से 1700 रुपए तक हो गए हैं। पिछले साल इसी समय रही 900 से 1000 रुपए की कीमत की तुलना में यह बड़ा इजाफा है। चूंकि स्पष्ट नहीं कि अगली खेप कब आएगी, तो यह अनिश्चितता बाजार के उतार-चढ़ाव और बढ़ा रही है।

ऐसे कठिन हालात में, पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद आप गर्मियों की छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो आपको ज्यादा खर्च के लिए तैयार रहना होगा। महंगाई ने लगभग हर देश को झटका दिया है। चाहे संघर्ष में सीधे शामिल देश हों या तटस्थ, दोनों ही प्रभावित हैं। भले बढ़ते हवाई किराए का समाधान अभी नहीं मिला हो, लेकिन कई समझदार यात्रियों ने रहने का खर्च घटाने का तरीका ढूंढ लिया है। जो आमतौर पर कुल यात्रा बजट का लगभग 42% होता है। उनका सीक्रेट है होम स्वैपिंग।

वर्षों से बजट के प्रति सचेत परिवार खर्च घटाने के लिए होटलों के बजाय एयरबीएनबी चुनते रहे हैं, जहां उन्हें प्राइवेट किचन, ज्यादा लिविंग स्पेस, लॉन्ड्री सुविधा मिलती है। होम स्वैपिंग में लगभग बिना किसी खर्च के ये फायदे और बढ़ जाते हैं। इसमें आप अपने घर को किसी दूसरे यात्री के घर से बदलते हैं।

शुरू में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गैर-पारंपरिक लग सकता है, पर आधुनिक शेयरिंग इकॉनोमी में ये लोकप्रिय हो रही हकीकत है। शुरू में होमएक्सचेंज, काइंड्रेड, पीपललाइकअस, होमलिंक, इंटरवैक या थर्डहोम जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ना होता है। होम एक्सचेंज इनमें प्रमुख है, जिसमें 2.50 लाख सदस्य हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपको लगभग 325 डॉलर की सालाना मेम्बरशिप फीस देकर अपने घर को 'अवेलबल फॉर एक्सचेंज' के तौर पर लिस्ट करना होता है। फिलहाल यह एक सीमित बाजार है, लेकिन कनाडा में इसमें 41% की बढ़ोतरी देखी गई है।

इस प्रक्रिया में दो फॉर्मेट हैं। एक साथ या अलग-अलग समय पर घरों का एक्सचेंज। जब दो पक्ष एक ही समय घर एक्सचेंज करते हैं तो 'साइमल्टेनियस स्वैप' होता है। मसलन, शिमला का परिवार मुंबई आए तो मेरे घर रुके, जबकि मेरा परिवार उनके शिमला के घर में छुट्टियां बिताए। दोनों मामलों में किराना व लॉन्ड्री सप्लाई जैसी जरूरी चीजें पहले से होती हैं, जिन्हें मेहमान जिम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं।

'नॉन साइमल्टेनियस स्वैप' में आप अपने घर में मेहमान ठहराते हैं और 'पॉइंट्स' कमाते हैं। बाद में उस मेहमान या किसी अन्य के घर पर ठहर कर पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें नकद में नहीं बदल सकते। इन प्लेटफॉर्म की सफलता सामुदायिक और भरोसे की भावना पर टिकी होती है।

लोग अपना ही घर साझा करते हैं तो इसमें पारस्परिकता का भाव बना रहता है। आप दूसरे के घर को उतनी ही सावधानी से रखते हैं, जितनी अपने घर के लिए उम्मीद करते हैं। साथ ही, मुफ्त में अच्छे घर में रहने का एहसास अकसर मेहमानों को प्रॉपर्टी की अतिरिक्त देखभाल के लिए प्रेरित करता है। यह तरीका ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, कनाडा, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, स्पेन और कई यूरोपीय देशों में पहले ही काफी लोकप्रिय हो चुका है। कुल मिलाकर, 2026 की गर्मियों में यात्रा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी होने वाली है।

फंडा यह है कि जेब पर अधिक बोझ डाले बिना अपनी ड्रीम वेकेशन को साकार करने के लिए आपको लागत कम करने के रचनात्मक तरीके ढूंढने होंगे। होम स्वैपिंग कोई अनोखा विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक यात्रियों के लिए एक बेहतर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है।

समता की पाठशाला में हो स्वतंत्र सोच का विकास

डॉ. संजय शर्मा

डॉ. बीआर अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, भागीदारी और समानता का कारगर औजार मानते थे। शिक्षा के बिना सामाजिक प्रगति संभव नहीं। ऐसे में स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी प्रकृति, संरचना और प्रक्रिया में आलोचनात्मक चिंतन का समावेश करें जिससे विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, समता के मूल्यों का सृजन हो।

बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने सार्वजनिक एवं सस्ती शिक्षा की अपरिहार्यता और महत्व के मद्देनजर लगभग सौ वर्ष पूर्व, सन् 1927 में बम्बई विधान परिषद में कहा था कि हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब समाज के निचले तबके के लोग भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेजों में दाखिला लेना शुरू कर रहे हैं। अत: शिक्षा विभाग की नीति होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा को निचले तबकों के लिए सस्ता और सुलभ बनाया जाए।

डॉ. अंबेडकर की दृष्टि में विद्यालय मात्र साक्षर बनाने का कोई प्रशासकीय उपक्रम नहीं, अपितु समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से परिष्कृत करने तथा समतामूलक भागीदारी के मौके प्रदान करने की सांगठनिक परियोजना है। भारत जैसे विषमतापूर्ण समाज में विद्यालय की भूमिका उन समुदायों के लिए खासकर अहम हो जाती है, जिन्हें व्यापक समाज-निर्माण की प्रक्रिया से दूर रखने को सुनियोजित सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम के तहत उनके शोषण को ज्ञान-शास्त्रीय वैधता दी गई। आज, विकसित होते भारत में डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हमें खुद से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम बाबासाहेब के सपनों की वह पाठशाला बना पाए हैं, जहां कक्षा के किसी कोने से एक बच्ची बिना डरे हाथ उठाती है, जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए। शिक्षक उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और पूरी कक्षा को चर्चा में शामिल होने का लोकतान्त्रिक वातावरण प्रदान करते हैं। वहां असहमति पर सज़ा नहीं, रट्टा मारने पर इनाम नहीं मिलता। दीवार पर नियमों की लंबी लिस्ट नहीं, केवल एक सरल वाक्य अंकित होता है 'राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान - सबके लिए शिक्षा एक समान'।

बाबा साहेब के आदर्शों के उस विद्यालय या कक्षा की कल्पना करे जो अभी हमारे समाज में अनुपस्थित है। यह महज़ कल्पना नहीं, मानवीय और संवेदनशील समाज होने की संज्ञानात्मक-कार्यात्मक कसौटी है।

जरा सोचिये, सामाजिक भेदभाव के कारण बालक भीमराव को स्वयं से पानी पीने की मनाही थी, उन्हें उस दिन विद्यालय में पानी नहीं मिलता था, जिस दिन उस विद्यालय में कार्यरत चपरासी छुट्टी पर होता। आज भी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के 23 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की बुनियादी सुविधा या तो मौजूद नहीं या बेहद सीमित है। मात्र 21 प्रतिशत विद्यालयों में ही नल के द्वारा पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, जबकि 70 प्रतिशत विद्यालय अभी भी हैंडपंप, कुएं आदि पर निर्भर हैं। आज़ाद भारत में भले ही सामाजिक दुराग्रहों को नियंत्रित कर लिया हो किन्तु व्यवस्थामूलक बहिष्कार अभी भी चुनौती है। आज भी अनेक बच्चे बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, पेयजल, शौचालय आदि से वंचित हैं। डॉ. अंबेडकर की अवधारणा थी कि भारत में जाति अर्थव्यवस्था, धर्म और राजनीति से पहले आती है और इन्हें नियंत्रित भी करती है। उनका यह दृष्टिकोण जाति को सत्ता और नियंत्रण की प्रणाली के रूप में देखता है।

बाबा साहेब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, भागीदारी और समानता का सबसे कारगर औजार मानते थे, जो दलितों और वंचित वर्गों को अज्ञानता, अंधविश्वास और शोषण से मुक्त करे। शिक्षा के बिना सामाजिक प्रगति संभव नहीं। ऐसे में शिक्षा केन्द्रों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रकृति, संरचना और प्रक्रिया में आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिकता का समावेश करें जिससे विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के मूल्यों का सृजन हो सके। इसके लिए जरूरी है कि विद्यालय समाज में व्याप्त जातीय असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ जरूरी हस्तक्षेप करे।

डॉ. अंबेडकर ने विद्यालय को समाज में व्याप्त निष्क्रियता एवं चुप्पी की संस्कृति को परिवर्तनकारी सक्रिय संस्कृति में रूपांतरित करने का प्रतिनिधि माना। अपनी पुस्तक 'जाति का उन्मूलन' में उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की वैचारिक आजादी ही उसकी असल स्वतंत्रता है। जो व्यवस्था अपने नागरिकों को सवाल पूछने से वंचित करे, वह अन्यायपूर्ण व गुलामी की सोच की पोषक है। बीते दशकों में न केवल पाठ्यक्रमों को बल्कि विद्यालयों के ढांचे को भी बहु-परती बनाते हुए विभाजनकारी स्वरूप प्रदान किया। जहां एक ओर सीखने-सिखाने के संसाधनों से परिपूर्ण उत्कृष्ट विद्यालय हैं वहीं दूसरी ओर बुनियादी संसाधनों के लिए जूझते आम सरकारी स्कूल भी हैं। पाठ्यक्रमों से कामगारों की अर्थव्यवस्था, श्रम व श्रमिकों की गरिमा, हाशिए पर जीने वाले समुदायों, वंचितों, महिलाओं के जीवन संघर्ष एवं अनुभव गायब हैं।

वस्तुत: राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता, जब तक उसके नीचे सामाजिक लोकतंत्र न हो। अंबेडकर की सोच में एक चेतावनी भी है, जो वर्तमान में प्रासंगिक है। संविधान सभा के अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कि हम विरोधाभासों से भरी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं- राजनीति में बराबरी लाएंगे, लेकिन सामाजिक-आर्थिक असमानता बनी रहेगी। बता दें कि शिक्षा प्रणाली में भी यही विरोधाभास कायम है। हमने भावी नागरिकों को विद्यालय तो मुहैया कराये किन्तु उनमें होने वाले बहिष्कारी अनुभवों को नहीं बदल सके। परिणाम, पाठशालाओं से केवल साक्षर नागरिक निर्मित हो रहे हैं, आलोचनात्मक नागरिक नहीं। सन 1943 में बाबा साहेब ने कहा था कि मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्यवैचारिक उत्थान और न्यायिक आदर्श की स्थापना होना चाहिए। यह लक्ष्य शिक्षा से हासिल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने समानता और समावेशन का विमर्श अपनाया है, लेकिन अंबेडकर के आदर्शों की सच्ची पाठशाला तभी बनेगी जब सुधार दस्तावेजों तक सीमित न रहकर विद्यालय की संस्कृति को वंचित समुदायों की उम्मीदों के शिक्षणशास्त्र में बदल दे। बाबासाहेब की जयंती पर शिक्षकों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वे अपनी कक्षाओं में निर्भयता से सवाल पूछने, स्वतंत्र सोचने और सामाजिक-नैतिक प्रश्नों पर सार्थक बहस का माहौल बनाएंगे।

लेखक डॉ. हरीसिंह गौर विवि, म.प्र. में सहायक प्राध्यापक हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

अवैध रूप से संचालित भवन को कराया गया कब्जा मुक्त

भिलाई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की शिकायत पर नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से संचालित एक भवन को कब्जा मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई जोन 3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में की गई। बेदखली टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद भवन को खाली कराते हुए उसे सील बंद कर अपने कब्जे में लिया गया। निगम आयुक्त राजीव पाण्डेय के निर्देशानुसार अधिकारियों को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिना हेलमेट ड्राइविंग : दो दर्जन पुलिस वालों का चालान

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती लगातार बढ़ रही है। अब ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 24 पुलिसकर्मियों पर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही उन्हें आगे से नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी गई है। यातायात पुलिस का कहना है कि, सड़क सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि जो लोग कानून लागू करवाते हैं, वे खुद भी उसका पालन करें।

पटरीपार न पानी, न सफाई, वोरा को बताई समस्याएं

दुर्ग। सोमवार सुबह पटरीपार क्षेत्र के एक वार्ड में पहुंचे पूर्व विधायक अरुण वोरा को वार्डवासियों ने घेर लिया और अपनी समस्याएं बताई। वोरा ने वहीं पर जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वार्डवासियों ने बताया कि उन्हें कई मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी आवश्यकता पटरीपार क्षेत्र मुक्तिधाम (श्मशान घाट) की है। वर्तमान में अंतिम संस्कार के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। पेयजल की नियमित सप्लाई नहीं होती। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। नालियां जाम पड़ी हैं। सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। स्ट्रीट लाइट की कमी और खराब स्थिति के चलते रात में अंधेरा छाया रहता है।

दुर्ग ग्रामीण में पंचायत स्तर पर बनेगी कांग्रेस की कार्यकारिणी

दुर्ग। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में बैठकें की गईं। इसका उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना और बूथ एवं पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठन को लेकर ठोस रणनीति तैयार करना रहा। जामुल, अंजोरा, कुथरेल, निकुम, उतई, पाऊवारा और नगपुरा में मंडल स्तर की बैठकें की गई। राकेश ने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन ही आगामी चुनावों में सफलता की कुंजी है।

केबल डालने के लिए खोदे गड्ढे में गिर रहे वाहन चालक

भिलाई। बोरसी कालोनी के प्रगति मैदान के पास एक माह से केबल डालने के लिए गहरा गड्ढा खोदा कर छोड़ रखा है, जिससे यहां बड़ा हादसा होने की संभावना है। सीमेंट के पाइप और ढक्कन भी लापरवाही पूर्वक छोड़ दिए गए है। कई बाइक सवार रात में यहां फिसल कर गिर चुके हैं। शिकायत करने पर अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं।

निगम ऐसा कर रहा विकास कि हितग्राहियों के निकल रहे आंसू; नाली सड़क दोनों बने मुसीबत

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में फिलहाल विकास की गाड़ी सरपट भाग रही है। कहीं सड़कें बनाई जा रही हैं तो कहीं नालियां खोदी जा रही हैं। न कोई योजना है, न कोई नक्शा - बस करोड़ों रुपए समय सीमा में खर्च करना का टारगेट है। बारिश से पहले किसी भी कीमत में ये दोनों कार्य पूरे किए जाने हैं। बेशक नालियां गलत दिशा में बनें, ऊंची सड़कों के कारण मकान डूब जाएं पर निगम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

रैंप बचाने गजब का स्टंट

पहला उदाहरण है वार्ड 13 साकेत नगर का। यहां नगर निगम द्वारा लगभग एक करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। फिलहाल यहां नाली निर्माण विवादों में है। पहले जेसीबी से सड़क के एक तरफ नाली खोद दी गई। पर एक नेता का घर रास्ते में आ गया। नाली निर्माण होने पर अतिक्रमण कर बनाया गया उनका रैंप कट जाता। इसलिए

खोदने का काम यहीं तक जाकर रुक गया। फिर नगर निगम के इंजीनियर आए और नाली दूसरी तरफ खोदने का निर्देश दे दिया। दूसरी तरफ के रहवासियों ने अपनी व्यवस्था खुद ही कर रखी थी। इधर नाली निर्माण की कोई जरूरत ही नहीं थी। पर निगम को किसी भी कीमत पर नाली बनवानी थी। इसलिए बनी बनाई नाली को तोड़कर अब फिर से नाली बनायी जा रही है। रहवासियों ने नगर निगम को पत्र भी लिखा पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

सड़क की वजह से डूबेंगे घर

दूसरी उदाहरण है, वार्ड-2 मॉडल टाउन का। यहां कंक्रीट की नालियां बनाई जा रही हैं। इससे उन सड़कों को तो राहत मिलेगी जहां पहले सड़क नहीं थी या बुरी तरह से टूट-फूट गई थी। पर जिन सड़कों का पहले ही कंक्रीटीकरण हो चुका है, उन्हें भी दोबारा बनाया जा रहा है। यहां संकट दूसरा है। इस वार्ड में कई मकान 30-35 या 40 साल तक पुराने हैं। जब पिछली बार सड़क बनी तो इनमें से कई मकानों का फर्श सड़क के समतल हो गया। बारिश का पानी घरों में घुसने लगा। अब यदि इन सड़कों की हाइट और बढ़ी तो बारिश में घर डूब जाएंगे। यही नहीं कंक्रीट नालियों की किनारी के कारण घर के सामने कार खड़ी करना भी मुश्किल हो गया है।

निर्माण की बेतरतीब प्लानिंग के चलते रास्ता हुआ बंद

मॉडल टाउन की सड़कें काफी लंबी हैं। इनमें से अधिकांश सड़कों का उत्तरी छोर एक तरफ से बंद है। निर्माण एजेंसी ने इसी छोर को मटेरियल गिराने के लिए चुना है। यहां ऊंची कंक्रीट की सड़क पर रेत और गिट्टी की ऐसी ढेरियां लगाई गई हैं कि लोगों का आनाजाना बंद हो गया है। अगर इन सड़कों पर किसी की तबियत बिगड़ी तो उसे उसी तरह बाहर ले जाना होगा जिस तरह बस्तर के दूरस्थ गांवों से मरीजों को सड़क तक लाया जाता था।

बीएसपी ने औद्योगिक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र ने उद्योग-अकादमिक समन्वय को सुदृढ़ करने तथा युवाओं की व्यावसायिक दक्षता को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मानव संसाधन- ज्ञानार्जन एवं विकास (एचआर- एल एंड डी) केन्द्र में व्यावसायिक प्रशिक्षुओं (वोकेशनल ट्रेनीस) के लिए औद्योगिक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम कक्षा आधारित शिक्षा एवं वास्तविक औद्योगिक कार्यप्रणाली के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक संरचित एवं समग्र उन्मुखीकरण मॉड्यूल के रूप में तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों को एकीकृत इस्पात संयंत्र की सुरक्षा प्रणाली एवं परिचालन तंत्र की व्यापक जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में गैस सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा एवं रेल आवागमन से संबंधित सुरक्षा उपायों जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के सही उपयोग पर विशेष बल देते हुए 'शून्य-हानि' (जीरो हार्म) कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को संयंत्र की जटिल एवं विस्तृत कार्यप्रणाली की समग्र समझ भी प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग ने देश के 187 प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया है, जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) तथा रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। यह सहयोग उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच प्रभावी समन्वय का सशक्त उदाहरण है।

भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनहित के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कुल 10 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा अनुशंसित इन कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भिलाई नगर के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जाएंगे।

इसमें मुख्य रूप से वार्ड क्रमांक 52, स्ट्रीट नंबर 03, सेक्टर 04 स्थित हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 2.00 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार, वार्ड क्रमांक 69, सेक्टर-09 भिलाई गोल मार्केट में स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2.50 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

अन्य विकास कार्यों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 70 हुडको कॉलोनी से वाय शेप ब्रिज तक लगे खंभों में रोप लाइट लगाने तथा राम चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 2.00 लाख रूपए स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त, वार्ड क्रमांक 68, सेक्टर 08 भिलाई फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे स्थित मंदिर के पास पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य हेतु 1.20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

हाइटेक हॉस्पिटल में पीलिया के अतिगंभीर मरीज का सफल इलाज, ऐसे मामलों में मृत्यु दर 95 फीसद तक

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। लिवर सिरोसिस के एक ऐसे मरीज का हाइटेक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल में सफल इलाज किया गया जिसकी हालत अत्यंत गंभीर थी। मरीज को अचेतावस्था में हॉस्पिटल लाया गया था। मरीज को निमोनिया भी था। शराब के आदि इस मरीज को पीलिया ने पूरी तरह से जकड़ रखा था। 10 दिन आईसीयू में वेन्टीलेटर पर रहने के बाद उसकी जान बच गई।

गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ आशीष देवांगन ने बताया कि 35 वर्षीय यह युवक शराब का आदि था। उसके लिवर की हालत अत्यंत खराब थी। रक्तचाप लगातार गिर रहा था। मरीज सांस नहीं ले पा रहा था। घर वालों के अनुसार मरीज का पेशाब भी बंद था। मरीज की छाती में संक्रमण था।

मरीज को तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया तथा उसे वेंटीलेटर पर डाला गया। लिवर सपोर्ट के लिए दवाइयां शुरू की गईं। निमोनिया और छाती के संक्रमण का इलाज प्रारंभ किया गया।

ऐसे मरीजों की सर्वाइल रेट बहुत कम होती है, लगभग 5 प्रतिशत। पर मरीज पर दवाइयों ने अच्छा असर दिखाया और 10 दिन बाद वह सकुशल आईसीयू से बाहर निकल आया।

डॉ देवांगन ने बताया कि मरीज का जीवन बचाने में छाती रोग विशेषज्ञ डॉ ए. अंसारी, इंटेंसिविस्ट डॉ मौसम खूबवानी, डॉ नीलिमा बम्बोडे एवं आईसीयू स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वैकल्पिक पानी का टैंकर प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 58 स्थित आईएचएसडीपी उरला के 80 एवं 81 नंबर ब्लॉक में लंबे समय से लो प्रेशर के कारण उत्पन्न पेयजल संकट को लेकर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस इलाके में प्रतिदिन पानी का टैंकर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर श्रीमती अल्का बाघमार के मार्गदर्शन में शहर में पानी की समस्या दूर करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।इसी क्रम में जल कार्य विभाग प्रभारी श्रीमती लीना दिनेश देवांगन ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गर्मी के दिनों में बढ़ती पानी की खपत तथा सिकोला टंकी से सप्लाई लाइन की दूरी के कारण पानी का प्रेशर कम हो रहा है, जिससे घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है और रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल कार्य प्रभारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने हैंडपंपों के जल स्तर की जांच कर बोरलाइन से पानी उपलब्ध कराने जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद रेशमा सोनकर भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर जल कार्य प्रभारी ने क्षेत्र की महिलाओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि जल संकट के स्थायी समाधान के लिए निगम प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसके तहत क्षेत्र में स्थित हैंडपंपों की जांच कर उनमें मोटर पंप लगाने तथा प्रत्येक क्वार्टर में सार्वजनिक नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना पर भी विचार किया गया।

सायकल पोलो में छत्तीसगढ़ महिला टीम चैंपियन

■ सीसीएफसी क्लब ऑल इंडिया इनविटेशन कप

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सीसीएफसी क्लब एवं सायकल पोलो एसोसिएशन ऑफ बंगाल द्वारा कलकत्ता में आयोजित सीसीएफसी आल इंडिया इनविटेशन कप में महिला वर्ग का फाइनल मैच छत्तीसगढ़ एवं केरल के मध्य खेला गया जिसमें छत्तीसगढ़ ने केरल को 14-05 के बड़े स्कोर से पराजित कर चैंपियनशिप अपने नाम की।

छत्तीसगढ़ से खेलने वाली पूनम ने सर्वाधिक 6 गोल किए, वहीं लक्ष्मी ने 4 गोल, खुशबू एवं रागनी ने 2-2 गोल किए। पुरुष वर्ग में तीसरे स्थान के लिए भारतीय प्रादेशिक सेना एवं छत्तीसगढ़ के मध्य मैच खेला गया जिसमें छत्तीसगढ़ टीम 13-3 के स्कोर से पराजित हुई।

पुरुष वर्ग में भारतीय वायु सेना प्रथम एवं भारतीय थल सेना द्वितीय स्थान पर रही। इस हेतु भारतीय साइकिल पोलो महासंघ के कोषाध्यक्ष तोषेंद्र वर्मा, भारतीय साइकिल पोलो महासंघ के पूर्व संयुक्त सचिव विनायक चन्नावार, बीएसपी साइकिल पोलो क्लब के अध्यक्ष परविंदर सिंह, बीएसपी साइक्लिंग क्लब तथा बीएसपी ओए के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर, छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ के अध्यक्ष डॉ रमेश श्रीवास्तव, दुर्ग जिला साइकिल पोलो संघ के सचिव शशांक देशमुख उपस्थित थे।

लायंस कांफ्रेंस : भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी ने बांधा समा

■ लायन डिस्ट्रिक्ट 3233सी का रीजन कॉन्फ्रेंस 'पहल' संपन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। भिलाई लयंस क्लब द्वारा शनिवार को लायन डिस्ट्रिक्ट 3233ष्ट के अंतर्गत रीजन 6 की बहुप्रतीक्षित रीजन कॉन्फ्रेंस 'पहल' का आयोजन भव्य एवं गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रीजन के सभी क्लबों के लायन सदस्य, पदाधिकारी एवं कवर्धा क्लब, बेमेतरा क्लब, महासमुंद क्लब व अनेक गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उद्घाटन सत्र में रीजन चेयरपर्सन पीएमजेएफ लायन शांतिलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने बड़े ही गर्मजोशी के साथ अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत किया।

ध्वज वंदना का पठन लायन सरिता दोषी द्वारा किया गया। भारत माता की वेशभूषा में लायन ज्योति लुनिया एवं छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में लायन शकुंतला साहू, लायन अंजुला सोनी एवं लायन पूजा साहू की प्रस्तुति सराहनीय रही।

मंचासीन पीडीजी त्रिलोक बराडिया, राजेंद्र तिवारी, नरेंद्र जैन, जयप्रकाश अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल ने संक्षिप्त उद्बोधन दिए। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पीएमजेएफ लायन विजय अग्रवाल ने सेवा कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने पर जोर दिया।

बिजनेस एवं रिपोर्टिंग सत्र में रीजन चेयरपर्सन द्वारा रीजन के सभी 12 क्लबों की गतिविधियों को पटल पर प्रस्तुत किया गया, जिससे रीजन 6 की सक्रियता एवं सेवा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से सामने आई।

लायन अनिल अग्रवाल के उद्बोधन ने सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

अवार्ड वितरण समारोह में उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले क्लबों एवं सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिससे सभी में उत्साह एवं प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार हुआ।

मंच संचालन लायन डॉ. रुचि सक्सेना द्वारा अत्यंत आकर्षक, प्रभावी एवं सुसंगठित ढंग से किया गया। उनके साथ जोन चेयरपर्सन लायन सीए मनोज सोनी ने समन्वय करते हुए संचालन को और अधिक प्रभावशाली बनाया।

उद्यमियों को रैम्प स्कीम के तहत बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट कार्यक्रम का प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। केंद्र सरकार की RAMP योजना के अंतर्गत, CSIDC छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, उन्हें बाजार से जोड़ने तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भिलाई नगर निगम में बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों को बाजार विकास हेतु आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना था। प्रतिभागियों को योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता, प्रदर्शनी एवं मेलों में भागीदारी, ब्रांड प्रमोशन तथा निर्यात के अवसरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

महिला उद्यमिता न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है।

कार्यशाला में बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम, योजनाएं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनी में भागीदारी की प्रक्रिया उत्पाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं लेबलिंग में सुधार आदि के साथ ही गुणवत्ता प्रमाणन एवं मानकीकरण के महत्व की जानकारी भी कार्यशाला के प्रतिभागियों को दी गई।

Since 1972
CROWN® TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

नक्सलमुक्त बस्तर में विकास की नई गूंजः मुख्यमंत्री साय ने सुकमा को दी 308 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नक्सलवाद के प्रभाव से उबरकर नए विश्वास और विकास की राह पर अग्रसर बस्तर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले को 308 करोड़ रुपए से अधिक के 228 विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 159 कार्यों का शिलान्यास और 69 कार्यों का लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति प्रदान की। मिनी स्टेडियम सुकमा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 40 वर्षों से नक्सलवाद के कारण पिछड़े रहे क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में बस्तर में शांति स्थापित हुई है और अब यहां विकास की गंगा बह रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिन गांवों में कभी हिंसा और भय का माहौल था, वहां आज स्कूलों की घंटियां गूंज रही हैं और लोग लोकतंत्र पर भरोसा जताते हुए मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 हजार से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उन्हें पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से नई जिंदगी की शुरुआत के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनआरएलएम स्टॉल में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनने के लिए प्रेरित किया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।

आवास, अधिकार और आजीविका– हर क्षेत्र में सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्टॉल में हितग्राहियों से बातचीत कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से 15 वनाधिकार पत्र वितरित किए गए, जिससे आदिवासी परिवारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वन विभाग के स्टॉल में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई। सहकारी समिति तोंगपाल को 4.27 लाख रुपए का सांकेतिक चेक दिया गया तथा एक हितग्राही को संग्रहण कार्ड वितरित किया गया। इसके साथ ही पुनर्वासित स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 2 ई-रिक्शा प्रदान कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया गया और एक हितग्राही को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया।

नियद नेल्लानार 2.0 और 8 बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत अब तक 500 से अधिक गांवों में 17 विभागों की 45 योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए गए हैं। इस योजना के अगले चरण 'नियद नेल्लानार 2.0' में अब 10 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं, जिनमें सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, बस स्टैंड, सामुदायिक भवन और मंदिर जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, सांसद महेश कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

स्वस्थ बस्तर की दिशा में बड़ा कदम

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को घर-घर तक सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की। इस अभियान के तहत 7 जिलों में 1100 टीमें घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेंगी। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री साय ने मिनी स्टेडियम में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम नागरिकों एवं हितग्राहियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता सामग्री और प्रमाण पत्र वितरित कर शासन की संवेदनशीलता का परिचय दिया। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री ने 7 टीबी मुक्त पंचायतों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और जानकारी ली कि जिले में अब तक 28 पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। उन्होंने 3 टीबी मरीजों से संवाद कर उन्हें पूछ बास्केट वितरित किया। मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए मरीजों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चश्मा पहनाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही दवा और आई ड्रॉप भी वितरित किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए मूर्तोंडा, पेंटा और कांकेरलंका उपस्वास्थ्य केंद्रों को एनक्वास सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग के स्टॉल में मुख्यमंत्री श्री साय ने आईईडी ब्लास्ट में पैर गंवा चुके 5 हितग्राहियों को कृत्रिम पैर प्रदान किए। इसके अलावा 4 व्हीलचेयर और 3 ट्राइसिकल भी वितरित किए गए तथा 6 दिव्यांगजनों को पहचान पत्र देकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई।

महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा उनका पूरा हक निर्णय प्रक्रिया में बढ़ेगी भागीदारी - मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'पंचायत से पार्लियामेंट तक' नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह प्रयास नए भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी ही विकसित भारत की सशक्त नींव है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में नारी को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भूमिका समाज के निर्माण और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमारी डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं ने इस परंपरा को आधुनिक संदर्भ में सशक्त रूप दिया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथ ही 'महतारी वंदन योजना' जैसी पहल माताओं-बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि जब देश में महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, उसी समय छत्तीसगढ़ 'महतारी गौरव वर्ष' मना रहा है। उन्होंने कहा कि 'छत्तीसगढ़ महतारी' का सम्मान और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी प्रदेश की पहचान बन चुकी है।

उन्होंने प्रदेश की मातृशक्ति और महिला संगठनों से आह्वान किया कि वे हर मंच पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस परिवर्तन यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

हर घर जल योजनाः छिबर्रा के 278 घरों में पहुंच रहा स्वच्छ पेयजल

रायपुर। महासमुंद जिले के विकासखंड पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत छिबर्रा में हर घर जल के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण जनों के जीवन में खुशहाली आई है। 30 दिसंबर 2025 को ग्राम छिबर्रा ने हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण कर यह उपलब्धि हासिल की है। गांव के कुल 278 घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल एवं आंगनवाड़ी जैसे सभी सार्वजनिक संस्थानों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे संपूर्ण गांव को स्वच्छ जल की सुविधा प्राप्त हो रही है। इस उपलब्धि में ग्राम पंचायत का नेतृत्व एवं ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रहा है।

योजना के सफल संचालन एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है।

- डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा
- खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्राथमिकता से होंगे कार्य

डीएमएफ से होगा कोरबा जिला का विकासः लखनलाल देवांगन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट कोरबा सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, पूर्ण कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया।

डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बैठक में डीएमएफअंतर्गत विशेष निधियों के अनुमोदन के साथ-साथ खनन प्रभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्रों के निर्धारण, प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित परिवारों की सूची के अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। इसके अलावा एंडोमेंट फंड के गठन तथा पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के प्रस्ताव, शासी परिषद ने डीएमएफअंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई के चयन, प्रशासनिक व्यय के अनुमोदन तथा वर्ष 2025-26 में किए गए कार्यों की स्वीकृति, खनन प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के चिन्हांकन एवं संबंधित विभागीय कार्यों के अनुमोदन, वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तथा 2025-26) के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए वेबसाइट, वेब पोर्टल, डाटा प्रबंधन प्रणाली, डॉक्यूमेंट्री एवं वेबपेज निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति, जीजीवी के साथ एमओयू, वीसी रूम एवं स्टोरेज संरचना निर्माण, थर्ड पार्टी ऑडिट तथा टोल-फ्री नंबर स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

इस अवसर पर कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत, कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल, पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह, महापौर संजू देवी राजपूत सहित शासी परिषद के सदस्यगण अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान डीएमएफ मद से संचालित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। अपने उद्बोधन में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिले में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अन्य योजनाओं के साथ-साथ डीएमएफ मद से भी कोरबा जिले में अतिरिक्त विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अनुमोदित कार्यों में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य सेवाएँ, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण तथा पुल-पुलियों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि स्वीकृत कार्यों का समय-सीमा में पूर्ण होना आवश्यक है, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने डीएमएफ के माध्यम से पीवीटीजी समुदाय के लिए प्राथमिकता से विकास कार्य संचालित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया।

मंत्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा करें, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें तथा नए प्रस्तावों को बजट प्रावधान के अनुरूप स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करें। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से समन्वयपूर्वक कार्य कर जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की अपील की।

सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ मद से कोरबा जिले को विकास की नई पहचान मिलेगी। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्र होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण, राखड़ बांधों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, बारिश से पहले स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने की आवश्यकता बताई।

विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने कहा कि डीएमएफ राशि से जिले में महत्वपूर्ण विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने आकांक्षी जिला होने के कारण कौशल विकास, आजीविका संवर्धन, रोजगार सृजन तथा कृषि क्षेत्र में दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर मरकाम ने डीएमएफ के तहत बनाए गए निर्माण पोर्टल को जनहित में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कंवर ने जिले में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन के लिए इंजीनियरों की भर्ती को उपयोगी कदम बताया। महापौर संजू देवी राजपूत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और जनसुविधाओं के विस्तार से आमजन को हो रहे लाभों का उल्लेख किया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बैठक के विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम बैठक है। शासन द्वारा डीएमएफ नियमों में संशोधन कर उन्हें इस वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। उन्होंने बैठक के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य खनन के दुष्प्रभावों को कम करना और प्रभावित लोगों की आजीविका एवं जीवन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने डीएमएफ के कार्यों को पारदर्शिता के साथ करने, निर्माण पोर्टल के माध्यम से डीएमएफ सहित अन्य विकास कार्यों की जानकारी मिलने के संबंध में बताया। डीएमएफ नियमों के तहत 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जाएगा तथा 30 प्रतिशत राशि अन्य आधारभूत संरचनाओं पर व्यय की जाएगी। जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित गांवों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिसके अनुसार 5 विकासखंडों के 564 गांव प्रत्यक्ष प्रभावित श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि खनन क्षेत्र से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र और 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा। इससे डीएमएफ की बड़ी राशि कोरबा जिले के प्रभावित क्षेत्रों में व्यय होगी।

उन्होंने बताया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सहयोग से खनन प्रभावित परिवारों का विस्तृत बेसलाइन सर्वे किया जा रहा है, जिसके आधार पर एक वर्ष की पर्सपेक्टिव योजना तैयार होगी। आंकड़ों के अनुसार एसईसीएल की विभिन्न खदानों से प्रभावित 20,069 परिवारों और 4,102 विस्थापित परिवारों के कल्याण हेतु योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

करोड़ों की लागत से बदल रहा पुसौर का स्वरूप-वित्त मंत्री चौधरी

वित्त मंत्री ने पुसौर में लाइब्रेरी, पुष्पवाटिका एवं तालाब सौंदर्यीकरण कार्यों का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी.चौधरी ने पुसौर में निर्माणाधीन लाइब्रेरी भवन, पुष्पवाटिका उद्यान, चंदन तालाब सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा

निर्माण स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से कार्यों की स्थिति देखना, बुनियादी ढांचे का विकास कराना हम सभी की जिम्मेदारी है द्य उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री चौधरी ने नगर पंचायत पुसौर के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आमजन को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही क्षेत्र का समग्र एवं संतुलित विकास संभव है। साथ ही उन्होंने पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने तथा विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।

उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत पुसौर में पुष्पवाटिका उद्यान निर्माण हेतु लगभग 2 करोड़ 92 लाख 40 हजार रुपये, बोरोडीपा चौक से कॉलेज तक बी.टी. रोड एवं नाली निर्माण के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपये, चंदन तालाब के सौंदर्यकरण के लिए 2 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये तथा लाइब्रेरी भवन निर्माण के लिए लगभग 99.12 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त तेलीतार तालाब के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य भी प्रगति पर है, जिससे क्षेत्र की सौंदर्य वृद्धि के साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर नगर पंचायत पुसौर के अध्यक्ष मानी मोहित सतपथी, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, एसडीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं नगर पंचायत पुसौर के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति थे ।

ईशा सिंह निभाएंगी ऑटिस्टिक लड़की की भूमिका जानिए एक्ट्रेस के अपकमिंग शो से जुड़ी पूरी डिटेल

ईशा सिंह और विजयेंद्र कुमेरिया की जोड़ी जल्द ही एक नए सीरियल में नजर आने वाली है। इनके अपकमिंग सीरियल का नाम है जूही। हालांकि, चैनल ने अभी प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी डिटेल आउट नहीं किया है।

रिपोर्ट के अनुसार इस सीरियल में एक नई और इमोशनल कहानी को दिखाई जाएगी, जिसमें ईशा सिंह और विजयेंद्र कुमेरिया अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस शो के जरिए बॉलीवुड एक्टर संजय सूरी भी टीवी पर डेब्यू करने जा रहे हैं, इस वजह से भी ये नया सीरियल चर्चा में बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार वो इस शो में जूही के पिता की भूमिका में नजर आएंगे। जो शो की कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट लेकर आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार इस सीरियल का प्रीमियर आईपीएल के बाद होगा। शो को लेकर अभी से ही दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

रिपोर्ट के अनुसार इस शो की कहानी जूही नाम की एक ऑटिस्टिक लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसका कैरेक्टर ईशा सिंह प्ले करने वाली हैं। शो की कहानी जूही की जर्नी पर बेस्ड होगी, वो एक ऐसे दुनिया में खुद को संभालती हुई नजर आएगी, जो उसे समझ ही नहीं पाती है।

शो में उसकी चुनौतियों और उसकी ताकत दोनों को दिखाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ईशा सिंह अपने रोल को बहुत ही सेंसेटिव तरीके से निभाएंगी। साथ ही ऑटिस्टिक लड़के के कैरेक्टर और उसकी भावनाओं को खूबसूरती के साथ स्क्रीन पर पेश करेंगी।

विजयेंद्र कुमेरिया इस शो में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जो जूही को सपोर्ट करेंगे। उसकी पर्सनल और सोशल दोनों जर्नी में उसका खूब साथ देंगे। वहीं जूही के पिता के कैरेक्टर में संजय सूरी कहानी को इमोशनल तरीके से जोड़ेंगे।

उनका कैरेक्टर एक ऐसे शख्स का होगा जिसकी बेटी ऑटिस्टिक होती है, जिसे लेकर उसे काफी चिंता होती है, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। अपनी बेटी के लिए वो दुनिया से लड़ सकता है, जिससे ये शो और भी ज्यादा रियल और इम्पैक्टफुल लगेगा।

'कल्कि संभल' का दूसरा पोस्टर जारी

1978 दंगों के पीड़ित सेठ बनवारी के रूप में दिखे रजनीश दुग्गल

संभल के इतिहास से जुड़ी एक संवेदनशील घटना पर बनी फिल्म 'कल्कि संभल' लगातार चर्चा में बनी हुई है। 1978 के संभल दंगों की पृष्ठभूमि पर तैयार हो रही यह फिल्म शुरुआत से ही सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस का केंद्र रही है। पहले पोस्टर के सामने आते ही जहां विवाद और चर्चाएं तेज हो गई थीं, वहीं अब मेकर्स ने दूसरा पोस्टर जारी कर दिया है, जिसके बाद बहस एक बार फिर गर्मा गई है।

इस बार फिल्म निर्माताओं ने दंगों से जुड़े एक अहम और दर्दनाक किरदार को सामने रखा है, जिसने उस दौर की पीड़ा और जख्मों को फिर से याद दिला दिया है।

रिलीज किए गए दूसरे पोस्टर में सेठ बनवारी लाल गोयल के किरदार से पर्दा उठाया गया है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सेठ बनवारी लाल गोयल 1978 के संभल दंगों में मारे गए प्रमुख पीड़ितों में शामिल थे। बताया जाता है कि वह उस समय 'मुरारी लाल एंड संस' नाम की एक प्रतिष्ठित फर्म के मालिक थे और संभल के जाने-माने उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी।

दंगों के दौरान भड़की हिंसा में सेठ बनवारी लाल गोयल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फिल्म में इस किरदार को अभिनेता रजनीश दुग्गल निभा रहे हैं। इस भूमिका के जरिए मेकर्स उस दौर की त्रासदी और आम लोगों पर टूटे हिंसा के कहर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे इतिहास के उस हिस्से को सामने लाने की कोशिश बता रहे हैं, जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया। वहीं, कुछ वर्ग फिल्म की मंशा और इसके संभावित असर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले फिल्म के पहले पोस्टर को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी विवाद हुआ था। फिल्म के निर्माण और इसके विषय को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी, जो अब दूसरे पोस्टर के बाद फिर से चर्चा में आ गई है।

रोजाना 5 मिनट का ब्रेथर ब्रेक आपको दिनभर रखेगा ऊर्जावान, इसके बारे में जानिए

आजकल की तेज-तर्रार जिंदगी में खुद पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। काम के बीच-बीच में ब्रेक लेना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह हमें ताजगी और ऊर्जा देता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में 5 मिनट के ब्रेथर ब्रेक को शामिल करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। यह एक सरल, लेकिन प्रभावी तरीका है खुद को ताजगी देने का।

गहरी सांस लेना

गहरी सांस लेना खुद को ताजगी देने का एक सरल और असरदार तरीका है। जब भी आप काम कर रहे हों और थकान महसूस करें, थोड़ी देर के लिए अपने काम से ब्रेक लें और गहरी सांस लें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और तनाव कम होता है। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होता है और आप फिर से तरोताजा महसूस करते हैं। इसे दिन में कई बार दोहराना फायदेमंद हो सकता है।

स्ट्रेचिंग करना

काम करते समय शरीर में अकडन् होना आम बात है, लेकिन इसे दूर करने के लिए कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अपने हाथ-पैरों को खींचें, गर्दन को घुमाएं और कमर को मोड़ें। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और मांसपेशियों की थकान कम होती है। स्ट्रेचिंग करने से आपका शरीर लचीला बनता है और आप फिर से ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। इसे रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करना आसान है।

हल्का चलना

हल्का चलना भी खुद को ताजगी देने का एक अच्छा तरीका है। ऑफिस में थोड़ी देर टहलना या सीढ़ियां चढ़ना आपके शरीर को सक्रिय रखता है और ऊर्जा बढ़ाता है। इससे आपका मन भी तरोताजा होता है और आप फिर से काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हल्का चलना न केवल शारीरिक बल्कि, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान है और इसके कई लाभ हैं।

पानी पीना

पर्याप्त पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। काम करते समय अक्सर लोग पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। हर घंटे में एक गिलास पानी पीने की आदत डालें, ताकि आपका शरीर तरोताजा रहे और थकान कम हो। इससे आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। पानी पीने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपका मन भी शांत रहता है।

ध्यान लगाना

ध्यान लगाना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। काम के बीच में कुछ मिनट ध्यान लगाने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। इसे रोजाना करने से हमारी एकाग्रता क्षमता बढ़ती है और हम अधिक ध्यान से काम कर पाते हैं। ध्यान लगाने के लिए किसी भी शांत जगह बैठकर आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। इसे नियमित रूप से करने पर इसका सकारात्मक प्रभाव महसूस होगा।

कार्तिक आर्यन की नई हीरोइन प्रीति मुकुंदन कौन हैं?

नागजिला से कर रहीं बॉलीवुड में एंट्री

अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी अगली रोमांचक फिल्म नागजिला को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फकार्तिक की नहीं, बल्कि उनके साथ नजर आने वाली अभिनेत्री प्रीति मुकुंदन की भी हो रही है।

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद प्रीति अब करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही इस फिल्म के जरिए अपना बॉलीवुड सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कौन हैं प्रीति मुकुंदन, आइए जानते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्माता प्रीति के चयन से बेहद खुश हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रीति मुकुंदन इस भूमिका के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। वो फिल्म में एक बड़े मजेदार और कॉमेडी से भरपूर किरदार में नजर आएंगी, जो कहानी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खुद प्रीति भी इस किरदार को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें दर्शकों के सामने अपना एक अलग अंदाज पेश करने का मौका मिल रहा है।

प्रीति एक अभिनेत्री, मॉडल और डांसर हैं, जो अब तक कई तेलुगू, तमिल और मलयालम भाषा की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। प्रीति ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2024 में तेलुगू हॉरर-कॉमेडी फिल्म ओम भीम बुश से की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म स्टार के जरिए तमिल सिनेमा में कदम रखा। उधर मैंने प्यार किया उनकी पहली मलयालम फिल्म थी। प्रीति को विष्णु मांचू और अक्षय कुमार अभिनीत तेलुगू फिल्म कन्नप्पा में भी देखा गया था।

क्या स्क्रीन के बहुत करीब बैठने से आंखें हो जाती हैं खराब? जानिए सही जानकारी

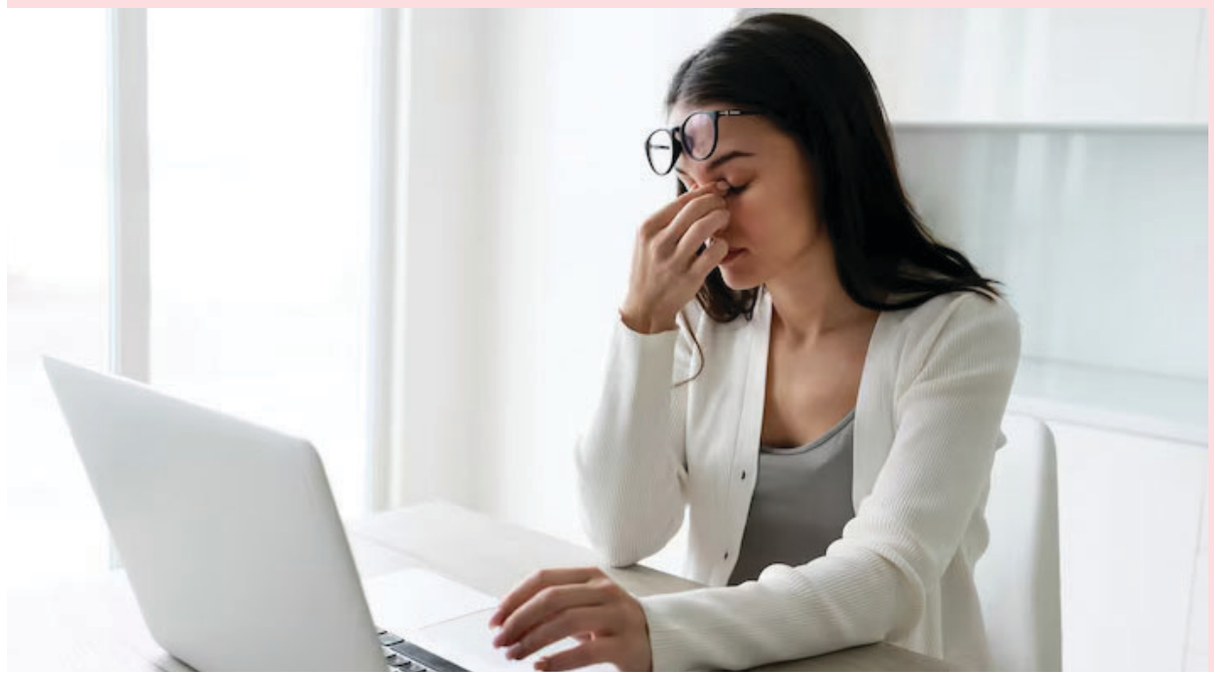

आंखों की देखभाल से जुड़े कई भ्रमों और बातों पर अक्सर चर्चा होती रहती है। इनमें से एक सामान्य बात यह है कि स्क्रीन के बहुत करीब बैठने से आंखें खराब हो जाती हैं। काफी लोग असमंजस में रहते हैं कि यह बात सच है या झूठ। इस लेख में हम इसी बात की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वास्तव में स्क्रीन के करीब बैठने से आंखों पर असर पड़ता है या नहीं।

स्क्रीन के करीब बैठने का आखों पर असर

जब हम बहुत करीब बैठकर किसी स्क्रीन आदि को देखते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियों पर ज्यादा जोर पड़ता है। यह जोर आंखों को थका सकता है और इसकी वजह से काफी परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसा करने से आपकी आखें वास्तव में काफी कमजोर हो सकती हैं। अगर आपको लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी नजर कमजोर हो रही है या आपको धुंधला दिख रहा है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।

क्या इससे कमजोर होती है आंखों की रोशनी?

कई लोगों का मानना है कि स्क्रीन के करीब बैठने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। यह बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि वक्त के साथ स्क्रीन टाइम का आखों की रोशनी पर खासा असर नजर आता है। अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं तो आंखों में थकान या जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, नियमित रूप से आराम करना और आंखों को आराम देना जरूरी है, ताकि नजर सही रहे।

क्या बच्चों को स्क्रीन के करीब बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए?

बच्चों को करीब बैठकर पढ़ाई करने से बचाना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं होतीं। इसके अलावा बच्चों को सही तरीके से बैठने और पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए, ताकि उनकी नजर सुरक्षित रहे। अगर बच्चे लगातार किताब के बहुत पास जा कर पढ़ाई करेंगे तो उनकी नजर कमजोर हो सकती है। इसलिए बच्चों को सही तरीके से बैठने और पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए।

कैसे कम किया जा सकता है प्रभाव?

आजकल लोग बहुत ज्यादा समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं, चाहे वह कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन। इससे आंखों में थकान या जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, नियमित रूप से आराम करना और आंखों को आराम देना जरूरी है। इसके अलावा स्क्रीन की चमक को कम करना और सही रोशनी में काम करना भी अहम है, ताकि आपकी नजर सुरक्षित रहे और कोई समस्या न हो।

नजर की जांच करवाना क्यों है जरूरी?

नजर जांच करवाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके। अगर आपको लगता है कि आपकी नजर कमजोर हो रही है या आपको धुंधला दिखता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इससे आप सही समय पर इलाज करा सकते हैं और अपनी नजर को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा नजर जांच करवाने से आप अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और किसी भी समस्या से बच सकते हैं।

खास खबर

महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा, दुर्ग तथा दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग के अंतर्गत संचालित 33 कृषि महाविद्यालयों, 04 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, 17 उद्यानिकी महाविद्यालयों, 01 वानिकी महाविद्यालय, 01 खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 01 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, 01 दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, 01 मत्स्य पालन महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 में दाखिले हेतु पी.ए.टी एवं पी.वी.पी.टी. प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रवेश परीक्षाओं हेतु 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 21 जून 2026 है। इन परीक्षाओं का आयोजन छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल नवा रायपुर द्वारा इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा।

खेती में डिजिटल क्रांति की नई उड़ान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एग्रीस्टेक परियोजना नई क्रांति का आधार बन रही है। इस परियोजना के अंतर्गत संचालित डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना ने राज्य में खेती-किसानी को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने का कार्य किया है। मोबाइल ऐप आधारित इस सर्वे के जरिए खरीफ और रबी फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है, जिससे कृषि प्रबंधन अधिक प्रभावी बन रहा है। खरीफ वर्ष 2025 के लिए 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ किए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे में राज्य के 33 जिलों के 18,008 गांवों के कुल 1 करोड़ 19 लाख 68 हजार 415 खसरों का सर्वेक्षण किया गया। इनमें से 1 करोड़ 18 लाख 07 हजार 537 खसरों को अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार 85 प्रतिशत खसरों का डिजिटल सर्वे कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। वहीं, रबी फसल वर्ष 2026 का सर्वे 1 जनवरी 2026 से जारी है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत राज्य के कुल 40 लाख 08 हजार 908 किसानों में से 31 लाख 68 हजार 555 किसानों का सत्यापन कर फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। यह कुल किसानों का 79.22 प्रतिशत है। राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 104 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' का भव्य शुभारंभ

युवा शक्ति ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति है- राजेश अग्रवाल

युवाओं को बजट और नीति-निर्माण से जोड़ने की राष्ट्रीय पहल, 30 हजार में से चयनित 471 प्रतिभागियों ने की सहभागिता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी में 'माय भारत बजट क्वेस्ट 2026' के भव्य शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही विकसित भारत की वास्तविक शक्ति है और यह आयोजन युवाओं को आर्थिक नीतियों और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त मंच प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित 'माय भारत' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय बजट 2026 के प्रति युवाओं और आमजन की समझ को सुदृढ़ करना है, ताकि बजटीय प्रावधानों को अधिक सुलभ, प्रासंगिक और नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके।

कार्यक्रम में देशभर से लगभग 30 हजार युवाओं में से चयनित 471 प्रतिभागियों की उपस्थिति इस आयोजन की व्यापकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।

मुख्य अतिथि अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बजट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश के विकास का रोडमैप होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस मंच का उपयोग सीखने, सोचने, प्रश्न पूछने और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए करें। उन्होंने कहा कि जब युवा नीति-निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं और उसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं, तब लोकतंत्र और अधिक सशक्त होता है। उन्होंने यह भी कहा कि करदाताओं के पैसे का उपयोग किस प्रकार और किन क्षेत्रों में हो रहा है, इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं को होना आवश्यक है, जिससे उत्तरदायित्व और जागरूकता की भावना विकसित होती है।

कार्यक्रम के दौरान माय भारत छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक श्री अर्पित तिवारी ने 'बजट क्वेस्ट 2026' की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह पहल युवाओं को वर्षभर रचनात्मक एवं राष्ट्रहित से जुड़े कार्यक्रमों में जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है और यह मंच युवाओं को अपने विचार रखने तथा नीति-निर्माण में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने जानकारी दी कि 'माय भारत' की घोषणा 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है, जो युवाओं के लिए, युवाओं के साथ और युवाओं द्वारा कार्य करती है, जिसका मूल मंत्र है - सेवा से संस्कार।

श्री तिवारी ने आगे बताया कि देश के सभी 763 जिलों में माय भारत कार्यालय स्थापित किए जाने की योजना है, जिनमें से छत्तीसगढ़ में 17 नए कार्यालय खोले जाएंगे। इन कार्यालयों के माध्यम से युवाओं का क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे आयोजनों के जरिए उन्हें सशक्त बनाया जाएगा।

ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के डायरेक्टर ओमप्रकाश व्यास ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि 30 हजार प्रतिभागियों में से चयनित 471 युवाओं का यहां उपस्थित होना उनकी प्रतिभा, परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यह मंच उन्हें सीखने, जुड़ने और देश के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करता है।

कार्यक्रम के समापन पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 जैसे आयोजन युवाओं को जागरूक, सक्षम और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए निरंतर प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर रायपुर नगर निगम आयुक्त विश्वदीप भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में माय भारत छत्तीसगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर नितिन शर्मा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) को राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023-2025 की मूल्यांकन अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मान के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

यह सम्मान राष्ट्रीय अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) नेटवर्क के अंतर्गत प्रदान किया गया। यह पुरस्कार रायपुर केंद्र की बहुआयामी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया जिसमें अनुसंधान परीक्षण, वैज्ञानिक प्रकाशन, प्रजनन नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास, किसान संपर्क कार्यक्रम और बीज उत्पादन शामिल हैं। यह पुरस्कार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) विश्वविद्यालय टीम के सदस्यों डॉ. सुनील कुमार नाग (प्रधान वैज्ञानिक), डॉ. रामा मोहन सावु (वरिष्ठ वैज्ञानिक) एवं डॉ. ऐश्वर्या टंडन (सह-प्राध्यापक) द्वारा प्राप्त किया गया। यह सम्मान डॉ. प्रताप सिंह, माननीय कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर; डॉ. एस.के. राव, पूर्व कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर; डॉ. के.एच. सिंह, निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर तथा डॉ. आर.के. माथुर, निदेशक, आईसीएआर-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद द्वारा 09 अप्रैल 2026 को हैदराबाद स्थित प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (सोयाबीन) की 56वीं वार्षिक समूह बैठक में प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने पुरस्कृत अनुसंधान दल के टीम लीडर एवं सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं।

यह पुरस्कार व्यापक मूल्यांकन प्रणाली और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर केंद्र ने असाधारण उपलब्धियाँ प्रदर्शित कीं। केंद्र ने लगातार तीन वर्षों तक पादप प्रजनन, सस्य विज्ञान, पादप रोग विज्ञान एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में सभी आवंटित परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए और उनकी स्वीकृति प्राप्त की। सोयाबीन अनुसंधान से संबंधित उच्च-गुणवत्ता वाले नास रेटेड शोध पत्र, सम्मेलन पत्र, बुलेटिन तथा एम.एससी. एवं पीएच.डी. छात्रों के मार्गदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

केंद्र ने सुदृढ़ जर्मप्लाज्म प्रबंधन (प्रति वर्ष 1000 से अधिक अभिग्रहण), व्यापक संकरण कार्यक्रम तथा आएसएसी 11-42, आएसएसी 11-72 और आएसएसी 12-32 जैसी उत्कृष्ट किस्मों के विकास में प्रगति की। प्रमुख उपलब्धियों में पूर्वी क्षेत्र के लिए तीन उन्नत सोयाबीन किस्मों का विकास, छह उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकों का विकास तथा तीन जर्मप्लाज्म लाइनों का पंजीकरण शामिल है। केंद्र ने प्रति वर्ष 100 फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन, कांकेर जिले में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने तथा नियमित किसान प्रशिक्षण एवं खेत प्रदर्शन के माध्यम से उत्कृष्ट विस्तार कार्य किया।

प्रजनक बीज उत्पादन में लगभग 90 : लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ न्यूक्लियस बीज उत्पादन में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई।

बदली जिंदगी, बढ़ा आत्मविश्वास रजनी उइके बनीं 'लखपति दीदी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अब केवल घरेलू दायित्वों तक सीमित न रहकर स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हो रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बतारी की निवासी श्रीमती रजनी उइके की सफलता की कहानी इसी परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है।

रजनी उइके ने स्नातक (बी.ए.) तक की शिक्षा प्राप्त की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे केवल गृहिणी बनकर सीमित नहीं रहना चाहती थीं, बल्कि अपने दम पर कुछ नया करने का संकल्प उनके मन में था। वर्ष 2022 उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब उन्हें बिहान योजना के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने 'जय लक्ष्मी स्व-सहायता समूह' से जुड़कर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

समूह से जुड़ने के पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा। स्व-सहायता समूह के माध्यम से उन्हें आरएफ मद से 8 हजार रुपए एवं सीआईएफ मद से 30 हजार रुपए की सहायता प्राप्त हुई। साथ ही बैंक से 1.5 लाख रुपए का ऋण लेकर उन्होंने अपने घर में ही पोल्ट्री फार्म, फोटो कॉपी एवं चॉइस सेंटर जैसे व्यवसायों की शुरुआत की।

श्रमिकों के पंजीयन हेतु मोबाईल कैम्प

कोण्डागांव। जिले के विभिन्न विकासखण्डों में श्रम विभाग के द्वारा मोबाइल कैम्प लगाकर श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण एवं योजनाओं का आवेदन प्राप्त कर निराकरण किया जाएगा। पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु आवश्यक मूल दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, बैंकपासबुक, मोबाईल साथ लायेंगे एवं असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु सरपंच या पार्षद द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। श्रमिक पंजीयन हेतु मोबाईल कैम्प का आयोजन कोण्डागांव विकासखण्ड के ग्राम पंचायत छोटेउसरी एवं नाहकानार में 15 अप्रैल 2026 को, ग्राम पंचायत फुकागिरोला एवं सिलाटी में 05 मई 2026 को, ग्राम पंचायत सोडसिवनी एवं तितना में 29 अप्रैल 2026 को, ग्राम पंचायत बड़ेसोंहगा एवं छिनारी में 20 मई 2026 को किया जाएगा।

जिला चिकित्सालय बेमेतरा में डायलिसिस यूनिट बनी किडनी मरीजों की जीवनरेखा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिला चिकित्सालय बेमेतरा में स्थापित आधुनिक डायलिसिस यूनिट किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय (एमसीएच) भवन में संचालित यह सुविधा अब तक 300 से अधिक मरीजों को जीवनदायी उपचार प्रदान कर चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा की शुरुआत 8 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 'जीवनधारा' के अंतर्गत की गई थी। प्रारंभ से ही यहां मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में यूनिट में 5 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें स्थापित हैं, जिनके माध्यम से अब तक 7,000 से अधिक डायलिसिस सेशन सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। प्रतिमाह औसतन 300 से अधिक सेशन संचालित हो रहे हैं, जबकि वर्तमान में 27 सक्रिय मरीज नियमित रूप से यहां उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

डायलिसिस यूनिट का नियमित निरीक्षण एम.डी. मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. अस्मिता श्रीवास्तव एवं सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू द्वारा किया जा रहा है। डायलिसिस टीम के अनुसार सभी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। मशीनों का नियमित परीक्षण एवं समय-समय पर मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ है। यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। डायलिसिस यूनिट की स्थापना से पहले मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय, धन एवं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। अब स्थानीय स्तर पर ही समय पर उपचार उपलब्ध होने से न केवल आपातकालीन परिस्थितियों में जीवनरक्षक सहायता सुनिश्चित हो रही है, बल्कि मरीजों एवं उनके परिजनों पर आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हुआ है। जिले के ग्राम द्वारा निवासी 51 वर्षीय श्रीमती कांति साहू ने बताया कि वह पिछले तीन वर्ष छह माह से डायलिसिस करवा रही हैं। पहले उन्हें मुंगेली और दुर्ग जाकर उपचार कराना पड़ता था, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में वह पिछले डेढ़ वर्ष से जिला चिकित्सालय बेमेतरा में सप्ताह में तीन दिन नियमित डायलिसिस करवा रही हैं।

मस्तूरी चिरायु टीम ने फिर बचाई एक मासूम की जिंदगी

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। मस्तूरी चिरायु (आरबीएसके) टीम ने फिर बचाई एक मासूम की जिंदगीछत्तीसगढ़ में चिरायु के नाम से प्रसिद्ध आरबीएसके टीम द्वारा एक बार फिर एक गरीब परिवार के बच्चे को नया जीवन मिला है। मस्तूरी चिरायु टीम पिछले कई वर्षों से लगातार स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 सप्ताह से 18 वर्ष तक के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है।

इसी क्रम में सीपत क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में 11 माह के एक बच्चे ध्रुवेश पुरी पिता नरेंद्र पुरी, माता ज्योति पुरी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जांच के दौरान बच्चा जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित पाया गया। चिरायु टीम ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को जिला अस्पताल में रेफर किया और स्वयं चिरायु वाहन से अस्पताल पहुंचाया। वहां ईको, ब्लड टेस्ट सहित सभी आवश्यक जांच कराई गई। इसके बाद बच्चे को रायपुर मेकाहारा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां जांच में बच्चे को कॉम्प्लेक्स सायनोटिक हार्ट डिजीज से पीड़ित पाया गया, जो एक गंभीर जन्मजात हृदय रोग है।

आगे की बेहतर चिकित्सा के लिए बच्चे को एम्स रायपुर एवं श्री सत्य साईं अस्पताल रायपुर में भी दिखाया गया। सभी रिपोर्ट्स को दिल्ली एम्स, अपोलो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल चेन्नई सहित विभिन्न उच्च स्तरीय अस्पतालों में भेजा गया। अपोलो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल चेन्नई के डॉक्टरों ने रिपोर्ट का अध्ययन कर बच्चे के ओपन हार्ट सर्जरी की सहमति दी। शुरुआत में परिजन ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चिरायु टीम ने लगातार काउंसलिंग कर उन्हें समझाया कि ऑपरेशन ही बच्चे के जीवन को बचा सकता है। अंततः माता-पिता तैयार हुए और टीम के सहयोग से 23 मार्च 2026 को बच्चे को चेन्नई भेजा गया। 25 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया और 1 अप्रैल 2026 को सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई। आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने गरीब परिवार की नन्ही बच्ची के सफल ऑपरेशन पर खुशी प्रकट की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चिरायु टीम को बधाई दी है इस पूरे कार्य में चिरायु नोडल डॉक्टर डॉ. सौरभ शर्मा, बिलासपुर सीएमएचओ डॉ शुभा गरेवाल,मस्तूरी बीएमओ डॉक्टर अनिल, बीपीएम भूपेंद्र देवांगन, डॉ मनीष सिंह, डॉक्टर सोनम धर्म बरगाह एवं पूर्णिमा सहित पूरी चिरायु टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बच्चे के माता-पिता ने स्वास्थ्य विभाग, चिरायु टीम एवं छत्तीसगढ़ शासन का दिल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए सच में जीवनदायिनी साबित हो रही है।

जल जीवन मिशन से बदली जीवन की तस्वीर, वनांचलों के दूरस्थ गांवों तक पहुंच रहा स्वच्छ पेयजल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जल जीवन मिशन वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन की तस्वीर बदल रही है। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के दूरस्थ व माओवाद प्रभावित रहे, पेयजल संकट से जूझने वाले टेकापानी गांव में अब जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से हर घर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। टेकापानी जैसे संवेदनशील गांवों में इस लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी उपलब्धि है।

जिला मुख्यालय कांकेर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित टेकापानी के लोग पहले पीने और घरेलू उपयोग के लिए नाले व झरिया के पानी पर निर्भर थे। गर्मियों में जलस्तर घटने पर महिलाओं को लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था। सरपंच सुदुराम कावड़े बताते हैं कि अब गांव में स्थापित सोलर आधारित जल आपूर्ति प्रणाली से हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। साथ ही जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है, जिसमें जल बहिनियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और गांव की महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत टेकापानी में 20 नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचने लगा है। गांव के ही पंप ऑपरेटर अनिल नूरेटी ने बताया कि अब गांववालों को नाले पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जीवन कहीं अधिक सरल हो गया है। जल जीवन मिशन से जल संकट समाप्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, जलजनित बीमारियों में कमी आई है।

CAR DECOR
House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बैंक रेट एवं ग्राहक उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, एक महिला समेत 2 की मौके पर मौत

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, यह हादसा पूंजीपथरा-घरघोड़ा मार्ग पर अमलीडीही गांव के पास हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर जा गिरे, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, मृतकों और घायल की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चिल्हाटी क्षेत्र के दुवालगुंडरा जंगल में मिले शव

राजनांदगांव। चिल्हाटी थाना क्षेत्र के दुलावगुंडरा जंगल में प्रेमी युगल की लाश फंदे पर लटकी मिली है। सोमवार सुबह आसपास के ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। मृतकों की पहचान शिवराजपुर निवासी काशीराम यादव (25) और औंधी क्षेत्र की रहने वाली दासू यादव (24) के रुप में हुई है। परिजनों ने बताया कि दोनों के बीच बीते 8 माह से प्रेम संबंध था। दोनों एक साथ भी रहने लगे थे। परिवार ने अगले महीने दोनों की सामाजिक रुप से शादी करने की भी तैयारी कर ली थी। शनिवार सुबह घर में दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोनों एक साथ ही घर से निकल गए। सोमवार सुबह जंगल में दोनों की लाश एक साथ फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने बताया कि आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। जबकि पूरा परिवार उनके सामाजिक शादी के लिए तैयार था। चिल्हाटी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी।

2 मामलों का खुलासा, चोर और दो बालक पकड़े गए

कोरबा। शहर के सीएसईबी कॉलोनी में रिटायर्ड एएसआई ग्लेडबिन कुमार व कोहड़िया में हंसराज खांडे के सूने मकान में चोरी के मामले में पुलिस ने चोर और उसके दो नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सीएसईबी कॉलोनी में पिछले मंगलवार रिटायर्ड एएसआई ग्लेडबिन कुमार बेटे की शादी के लिए बारात लेकर रायपुर गए थे। चोरों ने सूने मकान से 35 हजार व चांदी के सिक्के समेत 40 हजार की चोरी की थी। इसके दो दिन पहले कोहड़िया के पीपरपारा निवासी हंसराज खांडे के सूने मकान में चोरी हुई थी। वे वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गए हुए थे। सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पूछताछ के बाद तीन आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

मामा के बेटे के अपहरण का मास्टरमाइंड निकला भांजा

हनीट्रैप से फंसाया, कार से किडनैप कर 1 करोड़ फिरौती मांगी, युवती समेत 5 अरेस्ट

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 16 साल के लड़के को हनीट्रैप में फंसाकर किडनैप कर लिया गया। इसके बाद किडनैपरों ने उसके पिता को वीडियो भेजकर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड पीड़ित शख्स का सगा भांजा निकला। पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया है।

युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल, आरोपियों ने नाबालिग को किडनैप करने के लिए युवती का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम पर लड़की ने मैसेज करके नाबालिग को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे मिलने बुलाया और अपहरण कर लिया गया। यह मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के मुताबिक, अमलेश्वर निवासी ठेकेदार ने 12 अप्रैल 2026 को अमलेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा और भांजा तिरंगा चौक, अमलेश्वर बाइक बनवाने गए थे। इसी दौरान वहां एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार आकर रुकी। कार में बैठे एक व्यक्ति ने बेटे से बात की और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गया।

कॉल कर मांगी 1 करोड़ रुपए की फिरौती

करीब 45 मिनट बाद ठेकेदार के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके बेटे का अपहरण हो गया है और उसे छोड़ने के बदले 1 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो बेटे को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद फिर से कॉल आया, जिसमें खुद नाबालिग ने रोते हुए अपने पिता से उसे बचाने की गुहार लगाई। इसी बीच एक परिचित घर पहुंचा और उसने बताया कि उनके बेटे को एक कार में बैठाकर ले गए हैं। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

धमतरी पुलिस की मदद से पकड़ाया आरोपी

अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई। साइबर सेल की मदद से जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया था, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन धमतरी जिले के भखारा इलाके में मिली। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने धमतरी पुलिस से संपर्क किया।

रास्ते में जेसीबी अड़ाकर रोकी गाड़ी

धमतरी पुलिस ने अर्जुनी थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी। इसी दौरान एक संदिग्ध ग्रे सेंट्रो कार को रोका गया। रास्ता ब्लॉक करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई और सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया, ताकि गाड़ी आगे न जा सके। कार में बैठे लोगों से पूछताछ करने पर मामला संदिग्ध लगा। जांच में उसी कार से अगवा नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। साथ ही मौके से तीन आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। इसके बाद अमलेश्वर थाना और एसीसीयू की टीम वहां पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पूरे मामले का खुलासा किया।

सगे भांजे ने रची थी पूरी साजिश

जांच में पता चला कि ठेकेदार के भांजे संजय साहू (25) ने इस पूरे अपहरण की साजिश रची थी। उसे पता था कि उसके मामा के पास अच्छा पैसा है। इस प्लान में उसने अपने 3 दोस्त शैलेंद्र लहरे (25), रविंद्र लहरे उर्फ नानू (20), कृष्णा साहू उर्फ करन (28) को शामिल किया।

संजय ने इस साजिश में आरोपी युवती हेमपुष्पा साहू (24) को भी शामिल किया। प्लान के तहत करीब एक हफ्ते पहले हेमपुष्पा ने पहले नाबालिग से इंस्टाग्राम से जुड़ी। इसके बाद उसने बातचीत शुरू की। हेमपुष्पा ने 4-5 दिनों तक नाबालिग से प्यार भरी बातें की और उसे अपने जाल में फंसा लिया। फिर 12 अप्रैल को हेमपुष्पा ने उसे घूमने के बहाने अमलेश्वर के तिरंगा चौक बुलाया और वहां कार भेजी। जैसे ही नाबालिग कार में बैठा, उसे पहले से तय जगह ले जाया गया, जहां बाकी आरोपी पहले से मौजूद थे। इसके बाद सभी उसे लेकर धमतरी की ओर निकल गए और रास्ते में उसके पिता को फोन कर लगातार फिरौती मांगते रहे।

आरोपियों में भाई-बहन शामिल

पुलिस ने इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 भाई के साथ एक भाई-बहन भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शैलेंद्र लहरे, रविंद्र लहरे उर्फ नानू, कृष्णा साहू उर्फ करन, संजय साहू और हेमपुष्पा साहू हैं।

इनके पास से एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल, पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने पहले भी ऐसी कोई वारदात की है या नहीं।

नशे के कारोबार पर बड़ा वार, फरार आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में

श्रीकंचनपथ समाचार

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से अवैध अफीम की खेती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार था। लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया।

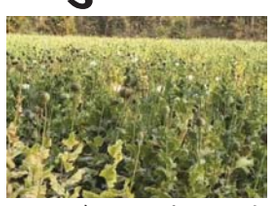

10 और 11 मार्च 2026 को इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी जहां संयुक्त टीम ने करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध अफीम जब्त की थी। इस कार्रवाई के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस पूरे मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और पुलिस लगातार इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुटी हुई है। पूरा मामला त्रिपुरी के ग्राम घोसराडांड से जुड़ा हुआ है जहां बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। कुसमी पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। नशे के खिलाफजारी इस कार्रवाई में अब अगला नंबर किसका पुलिस की नजरें पूरे नेटवर्क पर टिकी हैं।

26 लाख के गांजा के साथ 6 तस्कर पकड़ाए

श्रीकंचनपथ समाचार

जगदलपुर। जगदलपुर में पुलिस ने 54 किलो गांजा के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा को राजस्थान ले जाने के लिए सप्लाई की तैयारी में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 54 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 26.97 लाख रुपए है। साथ ही 6 मोबाइल फोन और कैश बरामद की गई है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, बस्तर पुलिस नशे के खिलाफलगातार अभियान चला रही है। बोधघाट पुलिस को 12 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि, राजस्थान से आए 4 लोग जगदलपुर के गोयल धर्मशाला में ठहरे हैं और सुकमा के 2 लोग उनसे मिलने गांजा लेकर पहुंचे हैं। सभी आरोपी कमरे में मौजूद हैं और गांजा को राजस्थान ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गोयल धर्मशाला के रूम नंबर 9 में रेड कार्रवाई की। रेड के दौरान कमरे में 6 लोग मिले। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 बैग में पैक 54 किलो गांजा बरामद किया गया। जिसकी कीमत करीब 26 लाख 97 हजार 200 रुपए बताई गई है।

इसके अलावा 6 मोबाइल फोन और 2,500 रुपए नगद भी जब्त किए गए। आरोपियों के पास गांजा रखने और परिवहन करने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद सभी आरोपियों के खिलाफ ,एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (B) के तहत मामला दर्ज कर 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी के नाम

बबलू कुशवाहा (राजस्थान)
श्रीनिवास (राजस्थान)
देशराज कुशवाहा (राजस्थान)
पंकज उपरेती (उत्तर प्रदेश)
राम सिंह (सुकमा)
दुबराज कश्यप (सुकमा)

ताश की गड्डी पर लग रहे थे दांव, तभी पुलिस की एंट्री और एक झटके में खत्म हो गई पूरी बाजी

श्रीकंचनपथ समाचार

कबीरधाम। जिले के लोहारा थाना क्षेत्र में जुआ खेल रहे लोगों की महफिल उस वक्त ताश के पत्तों की तरह बिखर गई जब पुलिस ने मौके पर दबिश देकर पूरे खेल को खत्म कर दिया, 13 अप्रैल 2026 को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना पर लोहारा पुलिस की टीम ने ग्राम जंगलपुर में अचानक रेड मारी जहां चार लोग ताश की गड्डी पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे।

पुलिस ने बिना मौका गंवाए सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया और मौके से 3200 रुपये नगद, 52 पत्ती ताश और एक अधजली

मोमबत्ती बरामद की, पकड़े गए आरोपियों में टिकेश्वर गुप्ता (26 वर्ष) निवासी बिरोडा, बीरेन्द्र निर्मलकर (24 वर्ष) निवासी बिरोडा, डेरहा यादव उर्फ पप्पू यादव (25 वर्ष) निवासी बिरोडा और देवव्रत वर्मा (30 वर्ष) निवासी जंगलपुर शामिल हैं, पुलिस ने फड़ और आरोपियों के कब्जे से जुआ सामग्री जब्त कर थाना स. लोहारा में अपराध क्रमांक 42/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 3(2) में मामला दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल और अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी कृष्ण कुमार चन्द्राकर के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा और उनकी टीम द्वारा अंजाम दी गई, पुलिस लगातार जिले में जुआ-सट्टा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है और साफ चेतावनी दी गई है कि ऐसे कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा, साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि कानून का खेल अब सख्त हो चुका है और इसमें कोई भी बाजीगर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा।

फांसी के फंदे से खींच लाई गई जिंदगी

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना उस वक्त जिंदगी की जीत में बदल गई जब आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने फंदे से उतारकर नई जिंदगी दे दी, 11 अप्रैल 2026 को ग्राम खोरपा वार्ड क्रमांक 14 निवासी 30 वर्षीय रवि ठाकुर सिकोला रोड किनारे बबूल की झाड़ियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बिना एक पल गंवाए त्वरित कार्रवाई की, हालात बेहद गंभीर थे, समय हाथ से निकल रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद योगेश

निक्की भाले, निशा सोनी, केवल देवांगन, जितेंद्र निर्मलकर और चंद्र प्रकाश देवांगन ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को फंदे से नीचे उतारा, रस्सी काटी और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, समय पर मिले इस जीवनदान ने मौत को मात दे दी और एक परिवार उजड़ने से बच गया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक ने व्यक्तिगत कारणों से यह कदम उठाया था, लेकिन जिस तेजी और मानवता के साथ जनप्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया दी उसने एक मिसाल पेश कर दी, इस सराहनीय कार्य को देखते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और उनके साहस की सराहना की।

पुलिस ने इस मौके पर आम जनता से भी अपील की कि किसी भी मानसिक तनाव या समस्या की स्थिति में आत्मघाती कदम न उठाएं बल्कि अपने परिजनों या नजदीकी पुलिस से संपर्क करें क्योंकि समय पर मदद ही जीवन बचा सकती है, यह घटना साफ बताती है कि जागरूकता और इंसानियत अगर साथ हो तो मौत के मुहाने से भी जिंदगी को वापस खींचा जा सकता है।

अवैध रेत उत्खनन पर बड़ा प्रहार: रात 1 बजे खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मशीन सहित 4 ट्रैक्टर जब्त

श्रीकंचनपथ समाचार

एमसीबी। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ एक्शन मोड में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर 10 अप्रैल 2026 की रात खनिज विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया।

रात्रि लगभग 1:00 बजे ग्राम पंचायत हरचौका, तहसील भरतपुर स्थित मवई नदी में स्वीकृत रेत खदान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय नियमों के विपरीत

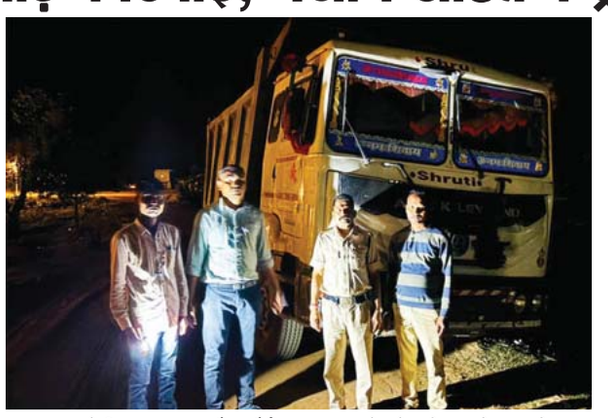

खनन कार्य किया जा रहा है। मौके पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने एक चौन माउंटेन मशीन और रेत से भरी एक हाईवा वाहन को तत्काल जब्त कर लिया।

कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सिरौली और चिउंटिमार क्षेत्रों में भी अवैध रेत परिवहन पर सख्ती दिखाई गई। यहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में संलिप्त 4 ट्रैक्टर वाहनों को पकड़ा गया। सभी वाहनों के मालिकों के खिलाफ खनन एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1), 21(5) एवं 23(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। जब्त किए गए चारों ट्रैक्टरों को कलेक्टरेट परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया है। इस पूरी कार्रवाई में खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा, खनिज सिपाही राजकुमार यादव सहित विभागीय अमले की सक्रिय भूमिका रही। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

तंबाकू पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 80 केस में कार्रवाई

रायगढ़। तंबाकू और सार्वजनिक धूम्रपान के खिलाफ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि एक ही दिन में 80 मामलों में कार्रवाई करते हुए 16,200 रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया और हुक्का पिलाते रेस्टोरेंट मैनेजर तक पुलिस की रेड पहुंच गई, 13 अप्रैल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में ऑपरेशन आघात चलाया गया, जिसमें Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA Act) के तहत बस स्टैंड, बाजार, शासकीय कार्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक जगहों पर सघन जांच अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।

पान दुकानों पर तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया तो वहीं खुलेआम धूम्रपान करने वालों को भी नहीं बख्शा

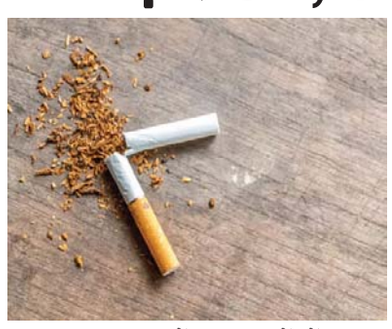

गया, थाना तमनार में 27 मामलों में 5,400 रुपये, धरमजयगढ़ में 17 मामलों में 3,400 रुपये, लैलूंगा में 16 मामलों में 3,200 रुपये, छाल में 11 मामलों में 2,200 रुपये, कापू में 7 मामलों में 1,400 रुपये और कोतरारोड़ में 2 मामलों में 600 रुपये की कार्रवाई कर कुल 80 प्रकरणों में 16,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी अभियान के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में साइबर और चक्रधरनगर थाना पुलिस ने सम्बलपुरी रोड स्थित बटर फ्लाई गार्डन/रेस्टोरेंट में दबिश दी जहां मैनेजर चंदन कुमार पत्रो (39 वर्ष) बिना किसी वैध अनुमति के आम लोगों को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के साथ हुक्का पिलाते पकड़ा गय।, जांच में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर पुलिस ने मौके से दो हुक्का पॉट, दो सेंटर बेस, चार पैकेट चॉकलेटी फ्लेवर तंबाकू और एक पाइप सहित करीब 8,000 रुपये का सामान जब्त किया और आरोपी के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में धारा 5/22 कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई, इस पूरी कार्रवाई में उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, संजय तिवारी सहित साइबर थाना और चक्रधरनगर की टीम सक्रिय रही, वहीं एसएसपी शशि मोहन सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि ऑपरेशन आघात के तहत कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू के अवैध उपयोग और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, बड़ा रेल हादसा टला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर-कटनी रेल सेक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बंट गई। गनीमत रही कि लोको पायलट की सतर्कता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार, पेंड्रा रोड और वेंकटनगर स्टेशन के बीच खैरझीटी बैरियर के पास अनूपपुर की ओर जा रही मालगाड़ी की कपलिंग अचानक टूट गई। इससे इंजन से जुड़े करीब 25 डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए और ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। स्थिति को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, जिससे ट्रेन को नियंत्रित कर लिया गया। अगर समय रहते ब्रेक नहीं लगाए जाते, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

प्रमुख खबरें

इनोवेशन महाकुंभ 1.0 के पोस्टर का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी स्थित निवास कार्यालय में इनोवेशन महाकुंभ 1.0 के पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कुलपति मनोज श्रीवास्तव और स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक जगदीश पटेल भी उपस्थित रहे। बस्तर के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और स्वरोजगार में तकनीक आधारित विकास हेतु इनोवेशन महाकुंभ 1.0 का आयोजन आगामी 4 एवं 5 मई को किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर और स्वावलंबी भारत अभियान, पीएम ऊषा एवं इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के साथ किया जाएगा। जिसमें एनआईटी रायपुर, आईआईएम रायपुर, आईआईटी भिलाई, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की भी सहभागिता होगी।

अवैध बाल आश्रम पर प्रशासन का एक्शन, बच्चों का रेस्क्यू

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार ग्राम चंपारण में अवैध रूप से संचालित बाल आश्रम पर संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम को प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम चंपारण स्थित एक बाल आश्रम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आश्रम में बच्चों को नियमों के विपरीत एवं असुरक्षित परिस्थितियों में रखा गया था। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई। बचाव किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां समिति के निर्देशानुसार उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत बालगृह में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया गया है। संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सुकमा में पुनर्वास से विकास की इबारत लिख रही डबल इंजन की सरकार

सुकमा में मुख्यमंत्री साय ने पुनर्वासितों को सौंपे मोबाइल फोन, आवास की चाबी और नियुक्ति पत्र

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नक्सल आतंक से मुक्त हुए सुकमा में अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिला मुख्यालय में संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने पुनर्वासित लोगों से संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भटके हुए लोगों को सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए दृढ़संकल्पित है। पुनर्वासितों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, तो हर भटका हुआ कदम नई दिशा और नया जीवन प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सल पुनर्वास नीति के चलते सुकमा सहित बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें से 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्थायी रोजगार और समाज में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक 307 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे आधुनिक जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सकें। विशेष रूप से 115 महिलाएं प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं।

कार्यक्रम के दौरान ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 नव नियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल, राजमिस्त्री किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया।

कवर्धा के जानकी वन धाम शिवालय में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जिला कबीरधाम अंतर्गत कुंआ-बिपतरा स्थित जानकी वन धाम में आयोजित नूतन शिवालय प्राण-प्रतिष्ठा एवं महायज्ञ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल विधायक भावना बोहरा के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देवाधिदेव महादेव का विधि-विधान से अभिषेक एवं पूजन कर समस्त चराचर जगत के कल्याण की कामना की।

शिवालय वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं की गहन आस्था से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे आयोजन से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।

कुंआ-बिपतरा क्षेत्र में स्थित जानकी वन धाम वर्तमान में एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं प्राकृतिक आस्था केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। घने जंगलों, हरियाली और शांत वातावरण से घिरा यह धाम श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। यहां पहुंचने पर जहां एक ओर आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य मन को आनंदित करता है।

स्वास्थ्य क्रांति : सुकमा में 'अटल आरोग्य लैब' का राज्यस्तरीय शुभारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिला चिकित्सालय में 'अटल आरोग्य लैब' का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया। यह पहल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आधार बनेगी, जो विशेष रूप से दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को आधुनिक एवं सुलभ जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य शासन का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिक तक उत्कृष्ट, किफायती और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। अटल आरोग्य लैब के माध्यम से अब प्रदेश के 1046 स्वास्थ्य संस्थानों - जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक -मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे लाखों नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

इस अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली के माध्यम से मरीजों को 133 प्रकार की जांचें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। जांच रिपोर्ट एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से सीधे मरीजों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बार-बार अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होगी और उपचार प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह व्यवस्था न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ भी बनाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की डायग्नोस्टिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इससे रक्त जांच सहित विभिन्न रोगों की पहचान शीघ्र और सटीक रूप से संभव होगी, जिससे समय पर उपचार शुरू कर मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में ऐसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि यहां के नागरिकों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। अटल आरोग्य लैब इस दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।

उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय सुकमा में पहले से ही ब्लड बैंक, सोनोग्राफी, एक्स-रे, ईसीजी, आपातकालीन सेवाएं, सीजेरियन प्रसव, एनआरसी एवं डायलिसिस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब अटल आरोग्य लैब के जुड़ने से यहां की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक हो जाएंगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, महिला आयोग सदस्य सुश्री दीपिका सोरी, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुंदरराज पी. सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बगीचा सीएचसी में एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत

जशपुरनगर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा में आज एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह पहल किशोरी बालिकाओं को गंभीर बीमारियों एवं विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के तहत ग्राम बगडोल निवासी पायल (14) को पहला एचपीवी टीका लगाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष से 15 वर्ष 3 माह तक की बालिकाओं को वैक्सीन लगाया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर बीपीएम, बीईटीओ, आरएमए, सेक्टर सुपरवाइजर, आरएचओ एवं एएनएम सहित स्वास्थ्य अमला उपस्थित था।

छत्तीसगढ़ शासन

मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन इस आधार पर करता हूं कि महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है।

— बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर

संविधान निर्माता, भारत रत्न

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी

को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

RO 47481/109

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950